वर्ष 13 • अंक 8 • 14 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

मंगलवार 25 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

शक्तिकांत दास ▸▸ पृष्ठ 4

बैंकों के अलग-अलग हो सकते हैं क्षेत्र

गौतम अदाणी ▸▸ पृष्ठ 3

एयर इंडिया के अधिग्रहण की दौड़ में अदाणी

डॉलर रु. 72.00 ▲ 30 पैसे | यूरो रु. 77.90 ▲ 60 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 43415 ▲ 1840 रुपये | सेंसेक्स 40363.20 ▼ 806.90 | निफ्टी 11829.40 ▼ 251.40 | निफ्टी फ्यूचर्स 11835.50 ▲ 06.00 | ब्रेंट क्रूड 55.60 डॉलर ▲ 02.30 डॉलर

एक नज़र

नई कंपनी बनाएगी हिंदुस्तान यूनिलीवर

तेल, साबुन जैसे रोजमर्रा के उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) ने सोमवार को कहा कि वह 2,000 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ एक नई सहायक कंपनी बनाएगी। एचयूएल ने एक बयान में कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल ने इसकी मंजूरी दे दी। इसका गठन तेजी से बदल रहे कारोबारी माहौल में अवसरों का उपयोग करने के इरादे से किया गया है। इससे एचयूएल और दक्ष और ग्राहक केंद्रित हो सकेगी।

क्रिसिल ने पीएनबी हाउसिंग को किया डाउनग्रेड

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने परिसंपत्ति गुणवत्ता में कमजोरी के कारण पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस की सावधि जमाओं की रेटिंग सोमवार को एएए से घटाकर एए कर दी क्योंकि कई बड़े डेवलपरों ने भुगतान में चूक की है। साथ ही इक्विटी जुटाने की योजना का आकार पहले के मुकाबले घटा दिया गया है। पीएनबी हाउसिंग का शेयर बीएसई पर 2.7 फीसदी की गिरावट के साथ 405.85 रुपये पर बंद हुआ।

वोडाफोन आइडिया का शेयर 12 प्रतिशत फिसला

भारती इन्फ्राटेल के इंडस टावर्स के साथ विलय की समयसीमा दो माह बढ़ाने से सोमवार को वोडाफोन आइडिया का शेयर 12 प्रतिशत फिसल गया। इस सौदे को पूरा होने में देरी से कंपनी को झटका लगा है क्योंकि उसे इंडस टावर में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री से करीब 5,500 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी। इंडस टावर में कंपनी की 11.15 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पृष्ठ 2

कोरोना से आया बाजार को रोना

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 24 फरवरी

सोमवार को दुनिया के शेयर बाजारों के साथ भारतीय बाजार में भी जबरदस्त बिकवाली देखी गई। कोरोनावायरस का कहर चीन के बाद यूरोप सहित दुनिया के अन्य देशों में पहुंचने से निवेशकों की नींद उड़ गई। कारोबारियों ने कहा कि निवेशक कोरोनावायरस के प्रकोप से वैश्विक अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान को लेकर चिंतित है और उन्हें लग रहा है कि हालात फिलहाल नहीं बदलेंगे।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 807 अंक की डुबकी लगाकर कर 40,363 तक फिसल गया और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) निफ्टी भी 242 अंक (2 प्रतिशत) टूटकर 11,839 के स्तर पर बंद हुआ। 1 फरवरी को पेश बजट के बाद बाजार में आई यह सबसे बड़ी गिरावट है। सेंसेक्स एवं निफ्टी में शामिल कंपनियों के साथ ही बीएसई के सभी क्षेत्रवार सूचकांकों में गिरावट देखी गई। इससे पहले नवंबर 2013 में निफ्टी की सभी कंपनियों में गिरावट देखी गई थी।

कोरोनावायरस को लेकर दक्षिण कोरिया द्वारा चेतावनी जारी करने के बाद निवेशकों का उत्साह और ठंडा पड़ गया। वहां इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 833 तक पहुंच गई है। खबरों के अनुसार इटली में केवल तीन महीनों में ऐसे मामले 150 से अधिक पहुंच गए हैं। हॉन्ग कॉन्ग के हैंग सेंग में भी 1.8 प्रतिशत गिरावट देखी गई, वहीं जर्मनी का डीएएक्स भी 3.8 प्रतिशत तक फिसल गया। यूनाइटेड किंगडम का एफटीएसई भी 3.6 प्रतिशत नीचे बंद हुआ, जबकि फ्रांस का सीएस 3.9 प्रतिशत नीचे चला गया।

मौजूदा हालात से चिंतित निवेशकों ने सुरक्षित समझी जाने वाली परिसंपत्तियों सोना आदि पर दांव लगाए। भारत में सोना 1,840 रुपये चढ़कर प्रति 10 ग्राम 43,415 रुपये हो गया। किसी एक दिन सोने में आई यह सबसे बड़ी तेजी है। ■ शेष पृष्ठ 3

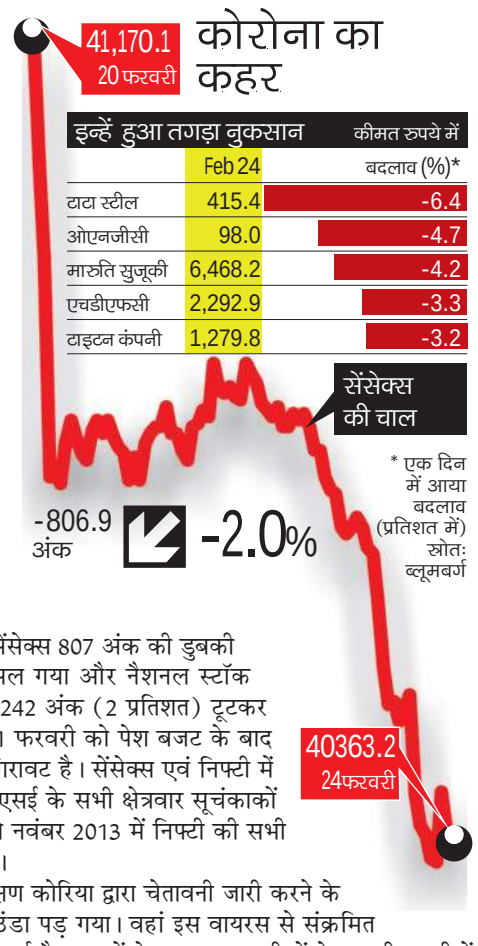

नमस्ते ट्रंप

फोटो : पीटीआई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी के राष्ट्रपति एवं उनकी पत्नी मिलानिया ट्रंप सोमवार को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में। मोदी ने ट्रंप दंपती को गांधी जी के तीन बंदरों वाला स्मृति चिह्न भेंट किया।

'मोदी सख्त, लेकिन सौदे की उम्मीद'

विनय उमरजी
अहमदाबाद, 24 फरवरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बीच आज यहां मोटेरा स्टेडियम में आयोजित 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम में गजब का तालमेल देखने को मिला। दोनों नेताओं ने जमकर एकदूसरे की तारीफों के पुल बांधे और भारत-अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का भरोसा जताया। ट्रंप ने कहा कि मंगलवार को दिल्ली में 3 अरब डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

ट्रंप ने स्टेडियम में मौजूद एक लाख से अधिक लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वह भारत के साथ खासकर रक्षा और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में करीबी संबंध चाहते हैं। मोदी को सख्त वार्ताकार बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा करेंगे। साथ ही कारोबारी समझौतों को व्यापक बनाने के बारे में भी बात होगी। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और मैं मिलकर एक शानदार समझौते पर पहुंच सकते हैं। ■ शेष पृष्ठ 14

डीएचएफएल घोटाला 25 हजार करोड़ का!

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 24 फरवरी

कर्ज में डूबी आवास वित्त क्षेत्र की कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनैंस (डीएचएफएल) का घोटाला 25,000 करोड़ रुपये का हो सकता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्राथमिक जांच में यह खुलासा हुआ है।

इससे पहले ईडी ने संदेह जताया था कि डीएचएफएल ने प्रवर्तक कपिल वधावन और धीरज वधावन से जुड़ी 79 मुखौटा कंपनियों

को 12,773 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे। यह राशि 2010 से 2015 के बीच करीब एक लाख फर्जी उपभोक्ताओं को खुदरा ऋण की आड़ में भेजी गई थी। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें डीएचएफएल और वधावन बंधुओं के बीच लेनदेन के कम से कम एक दर्जन नए मामलों का पता चला है। इनमें से कुछ लेनदेन प्रवर्तकों द्वारा शीर्ष पांच कंपनियों के जरिये डीएचएफएल के शेयरों की कीमतों के साथ की गई छेड़छाड़, निजी क्षेत्र के येस बैंक के साथ कुछ ऋण और निवेश, उचित कार्यवाही के बिना 30 कंपनियों को दिया गया संदिग्ध ऋण, मुंबई के कारोबारी सुधाकर शेट्टी के साथ करीबी संबंध और कुछ रियल एस्टेट सौदे से जुड़े हैं। ■ शेष पृष्ठ 3

महंगे होंगे पेप्सी, कोका-कोला

अर्णव दत्ता
नई दिल्ली, 24 फरवरी

अगर आप शीतल पेय के शौकीन हैं तो तैयार हो जाएं क्योंकि शीतल पेय कंपनियां आपकी जेब पर बोझ बढ़ाने जा रही हैं। इसकी वजह यह है कि एक लंबे अंतराल के बाद शीतल पेय कंपनियों ने अपने विभिन्न उत्पादों की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है।

अमेरिका की दो दिग्गज कंपनियां कोका-कोला और पेप्सिको गर्मी परवान चढ़ने से पहले कीमतों में 6 से 14 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही हैं। इन दोनों कंपनियों का भारत के शीतल पेय बाजार में 80 प्रतिशत हिस्सेदारी पर कब्जा है। पिछले कुछ वर्षों में स्पेसिफिक शेल्फ कीपिंग यूनिट्स (एसकेयू) की कीमतें मामूली रूप से जरूर बढ़ी हैं, लेकिन 2014 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब ये कंपनियां शीतल पेय की विभिन्न श्रेणियों में कीमतें बढ़ाएंगी।

सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोका-कोला, थम्स अप, स्प्राइट, पेप्सी कोला और 7अप की 600 मिलीलीटर की बोतलें अब 8.6 प्रतिशत महंगी हो जाएंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एसकेयू की संशोधित कीमतें 38 रुपये रखी गई हैं, जो पहले 35 रुपये में मिलती थी। माउंटेन ड्यू जैसे कुछ ब्रांड की कीमतें 14.3 प्रतिशत तक बढ़कर 40 रुपये तक पहुंच सकती हैं। इसी तरह, सभी लोकप्रिय ब्रांड के दो लीटर की बोतल की कीमत 90 रुपये हो जाएंगी, जो पहले 85 रुपये में मिलती थी। 1.25 लीटर बोतल अब 60 के बजाय 65 रुपये मिलेगी। 200 और 300 मिलीलीटर मात्रा वाली बोतल की कीमतें क्रमश: 12 और 15 रुपये पर बरकरार रहेंगी।

कंपनियां उन उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर कांच की बोतल में शीतल पेय बेचती हैं, जो अधिक खर्च नहीं करना चाहते हैं। कीमतों में बढ़ोतरी की जद में इन कंपनियों के उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा आ जाएगा। पेट (प्लास्टिक की बोतल) और कैन शीतल पेय उद्योग की कुल बिक्री में 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं।

कीमतें बढ़ाने के निर्णय पर पेप्सिको इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, 'हम समय-समय पर बाजार में बदलते हालात और उपभोक्ताओं की पसंद पर नजर रखते हैं। हमें जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं, उनके अनुसार हम कीमतों को लेकर निर्णय लेते हैं।'

दिल्ली में संशोधित कीमत	प्रतिशत	बदलाव
200/300 मिलीलीटर कांच बोतल	अपरिवर्तित	–
600 मिलीलीटर पेट	38-40 रुपये	8.6 से 14.3 प्रतिशत
1.25 लीटर पेट	65 रुपये	8.3 प्रतिशत
2 लीटर पेट	90	5.9 प्रतिशत

नोट: भारत के शीतल पेय बाजार में पेट की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक है।

जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद भी इन कंपनियों ने कीमतें नहीं बढ़ाई थीं। कुछ एसकेयू की कीमतें बढ़ाकर उन्हें कुछ हद तक बढ़ी लागत कम करने में मदद मिली थी। हालांकि कर में इजाफा होने से उनका मुनाफा जरूर फिसलने लगा था।

उदाहरण के लिए कोका-कोला की इकाई हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरिजेज को 2017-18 में 118 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान हुआ था। इन कंपनियों ने 6 वर्ष पहले कीमतें बढ़ाई थीं। तब से कच्चे माल जैसे चीनी की कीमतें खासी बढ़ गई हैं। इसके साथ ही पिछली कई तिमाहियों में इसके प्रदर्शन को देखते हुए कोका-कोला को कीमतें बढ़ाने की हिम्मत दी होगी। कम से कम 2018 के अंत से भारतीय संयंत्र का कारोबार समान गति से आगे बढ़ा है।

खबरों में रहे स्टॉक

अरबिंदो फार्मा

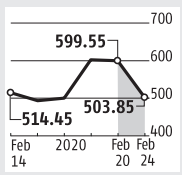

यूएसएफडीए ने यूनिट4 को स्वैच्छिक कार्रवाई शुरू करने का दर्जा वापस लिया

₹ 599.55 पिछला बंद भाव
₹ 503.85 आज का बंद भाव
▼ 15.96 %

जिंदल स्टील ऐंड पावर

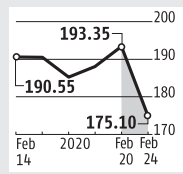

निफ्टी धातु सूचकांक में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर

₹ 193.35 पिछला बंद भाव
₹ 175.10 आज का बंद भाव
▼ 9.44 %

जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर

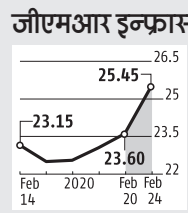

फ्रांस के हवाई अड्डा ऑपरेटर संग रणनीतिक साझेदारी

₹ 23.60 पिछला बंद भाव
₹ 25.45 आज का बंद भाव
▲ 7.84 %

अंबुजा सीमेंट्स

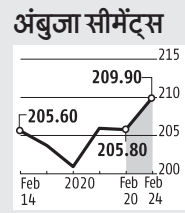

दिसंबर तिमाही में कर पूर्व लाभ 43 फीसदी बढ़ा

₹ 205.80 पिछला बंद भाव
₹ 209.90 आज का बंद भाव
▲ 2.00 %

हीरो मोटोकॉर्प

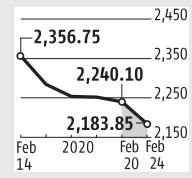

चीन में कोरोनावायरस की स्थिति पर निर्भर करेगा उत्पादन का नुकसान

₹ 2,240.10 पिछला बंद भाव
₹ 2,183.85 आज का बंद भाव
▼ 2.51 %

संक्षेप में

एचसीएल इन्फोसिस्टम्स के एमडी ने दिया इस्तीफा

एचसीएल इन्फोसिस्टम्स ने सोमवार को कहा कि उसके प्रबंध निदेशक राघवन रंगराजन ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने बताया कि रंगराजन ने निजी कारणों का उल्लेख करते हुए अपना इस्तीफा सौंपा है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज को को दी जानकारी में कहा गया है कि एचसीएल इन्फोसिस्टम्स के निदेशक मंडल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। रंगराजन का इस्तीफा 31 मार्च, 2020 से प्रभावी होगा। *भाषा*

अभय कुमार एनएचपीसी के नए चेयरमैन, एमडी बने

सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी एनएचपीसी ने सोमवार को अभय कुमार सिंह को कंपनी का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाए जाने की घोषणा की। *भाषा*

एजीआर पर साथ आने की तैयारी

गेल इंडिया एजीआर मामले में गैर-दूरसंचार कंपनियों को साथ लाने की कोशिश में

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 24 फरवरी

गेल इंडिया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के विवादित मामले में एक साझा कानूनी रुख अख्तियार करने के लिए अन्य सरकारी कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। गेल फिलहाल इस मुद्दे पर ऑयल इंडिया (ओआईएल) और पावरग्रिड कॉरपोरेशन (पीजीसीआईएल) के साथ चर्चा कर रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस महीने के आरंभ में गेल इंडिया को इस संदर्भ में एक उपयुक्त फोरम बनाने का निर्देश दिया था। दूरसंचार विभाग ने ब्याज एवं जुर्माना सहित वार्षिक लाइसेंस शुल्क के लिए कंपनियों से 1.83 लाख करोड़ रुपये की मांग की है। यदि इतनी बड़ी रकम का भुगतान किया जाता है तो इससे अगले पांच वर्षों के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च संबंधी कंपनी की योजना प्रभावित हो सकती है। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि हमें उतनी बड़ी रकम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।' कंपनियों को कानूनी विकल्पों के बारे में निर्णय लेना अभी बाकी है। इन विकल्पों में दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) में अपील करना भी शामिल है।

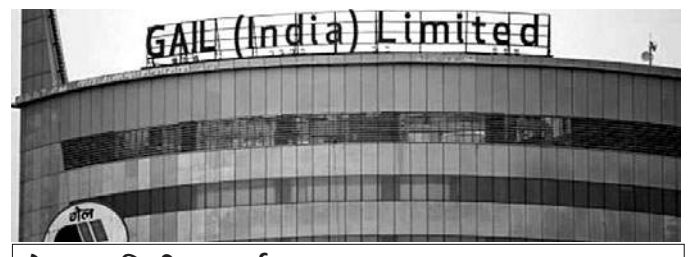

गेल का वित्तीय प्रदर्शन (एकल आधार पर) (रुपये/करोड़)

	2016	2017	2018	2019	2020
कुल कारोबार	52,003	48,789	53,690	74,808	54,021
कर बाद मुनाफा	2,226	3,503	4,618	6,026	3,602

36,882 करोड़ रुपये भंडार एवं अतिरिक्त (2018-19)

स्रोतः गेल

क्षमता विस्तार संबंधी कंपनी की करीब 50 फीसदी योजना उसके पारेषण कारोबार से संबंधित है। इसके लिए सरकार एक प्रस्ताव पर पहले से ही काम कर रही है जिसके तहत एक अलग सहायक इकाई बनाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा, 'हमने अगले पांच वर्षों के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है। इसमें से करीब 50,000 करोड़ रुपये का निवेश पारेषण कारोबार में किया जाएगा जबकि 10,000 करोड़ रुपये पेट्रोरसायन कारोबार में और 40,000 करोड़ रुपये का निवेश संयुक्त उद्यम में विस्तार पर किया जाएगा।' इसके तहत कंपनी अपनी मौजूदा क्षमता में 7,000 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क जोड़ेगी। गेल की नजर 2025 तक अपने राजस्व को दोगुना और मुनाफे को डेढ़ गुना करने पर है। यह निवेश सरकार की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत 2025 तक 5 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही गई है। साथ ही सरकार कुल ऊर्जा बास्केट में गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15 फीसदी करना चाहती है। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि अगले पांच वर्षों में पारेषण कारोबार की हिस्सेदारी कहीं अधिक होगी क्योंकि तब तक प्राकृतिक गैस की मांग में 6 से 8 फीसदी की वृद्धि होने का अनुमान है। जैन ने कहा कि सरकार एक प्रस्ताव पर काम कर रही है जिसके तहत पारेषण के लिए 100 फीसदी हिस्सेदारी वाली एक सहायक इकाई बनाने की योजना हैऔर मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के एक साल के भीतर नई कंपनी स्थापित हो जाएगी। गेल दाभोल में 50 लाख टन एलएनजी क्षमता के संयंत्र का परिचालन करती है और वह दाभोल में टर्मिलन के निर्माण के लिए लार्सन ऐंड टुब्रो को पहले ही ठेका दे चुकी है।

एजीआर गणना के लिए मांगे दस्तावेज

दूरसंचार विभाग के सूत्रों के मुताबिक सरकार ने दूरसंचार कंपनियों से एजीआर के स्व-मूल्यांकन की पुष्टि करने वाले दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है, जिसके आधार पर उन्होंने अपने ऊपर सांविधिक बकायों की गणना की है।

सूत्रों ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इस कवायद से दूरसंचार विभाग को दूरसंचार कंपनियों द्वारा की गई एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) गणना का की जांच करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि सभी तीन दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज से उनके एजीआर के स्व-आकलन के दावों की पुष्टि में दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है।

इंडस टावर्स संग विलय का समय बढ़ाया

एजेंसियां
नई दिल्ली, 24 फरवरी

भारती इंफ्राटेल ने इंडस टावर्स के साथ विलय की समयसीमा दो महीने और बढ़ाकर 24 अप्रैल तक कर दी है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। हालांकि कंपनी का कहना है कि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय कंपनी का निदेशक मंडल दूरसंचार क्षेत्र के संकट और उसके प्रभाव का आकलन करके लेगा। भारती इन्फ्राटेल ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया, इस विलय योजना को क्रियान्वित करने पर अंतिम निर्णय निदेशक मंडल कंपनी और हितधारकों के हितों को ध्यान में रखकर लेगा। साथ ही दूरसंचार उद्योग के मौजूदा संकट और उसका कंपनी के बड़े ग्राहकों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन भी निदेशक मंडल के निर्णय का आधार होगा। कंपनी ने बताया कि इंडस टावर्स के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति मिल गई है। कंपनी के विलय के लिए अंतिम तिथि पहले 24 फरवरी थी जिसे अब दो महीने बढ़ाकर 24 अप्रैल 2020 कर दिया गया है।

वोडाफोन आइडिया का शेयर 12 फीसदी टूटा

भारती इन्फ्राटेल द्वारा इंडस टावर्स संग विलय की समय-सीमा को 2 महीने बढ़ाकर 24 अप्रैल किए जाने के बाद सोमवार को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 12 फीसदी लुढ़क गया। इस सौदे को पूरा होने में देरी से वोडाफोन आइडिया को झटका लगा है क्योंकि इंडस टावर में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री से उसे करीब 5,500 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद थी। इंडस टावर में वोडाफोन आइडिया की हिस्सेदारी 11.15 फीसदी है।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज पर दिन भर के कारोबार के दौरान वोडाफोन आइडिया का शेयर 13.18 फीसदी की गिरावट के साथ 3.82 रुपये रह गया जबकि अंत में 11.82 फीसदी के नुकसान के साथ 3.88 रुपये पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर 13.86 फीसदी बढ़त दर्ज करने के बाद इस खबर के आने से 13.18 फीसदी तक लुढ़क गया। एनएसई पर भी लगभग यही स्थिति दिखी जहां यह शेयर 5.05 रुपये की ऊंचाई से लेकर 3.80 रुपये के निचले स्तर के दायरे में रहने के बाद अंतत: 12.50 फीसदी की गिरावट के साथ 3.85 रुपये पर बंद हुआ।

विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होगा भारत

पवन लाल
मुंबई, 24 फरवरी

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने मुंबई के एसटी रेजिस होटल में सोमवार को अनौपचारिक बातचीत की। उन्होंने कारोबारी परिदृश्य में बदलाव, बीते वर्षों में दूरसंचार कंपनियों की प्रगति और एक डिजिटल देश के रूप में भारत के संभावित भविष्य आदि को लेकर चर्चा की। इस 'फ्यूचर डिकोडेड सीईओ समिट' में 150 सीईओ ने हिस्सा लिया।

नडेला ने पहले दर्शकों के सामने अकेले ही प्रस्तुति दी थी। उन्होंने भारत में 56 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं, 45 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ताओं और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप तंत्र को मद्देनजर रखते हुए देश में बढ़ती डिजिटल संभावनाओं के बारे में बातचीत की। नडेला ने अंबानी को चर्चा के लिए मंच पर बुलाने से पहले कहा कि भारत युवा देश है, जिसमें 65 करोड़ लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। नडेला ने कहा कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग 180 अरब डॉलर का है।

अंबानी ने भरोसे, समानुभूति, साझेदारी पर आधारित नडेला की नेतृत्व शैली की प्रशंसा की। अंबानी ने कहा, 'आपने भारत को लेकर जितनी बड़ी प्रतिबद्धता जताई है, उसे लेकर कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसा करेगी। इससे मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूं। हम जियो और माइक्रोसॉफ्ट की साझेदारी को लेकर उत्साहित हैं। यह अहम बदलावकारी साझेदारी होगी। इसलिए भारत को लेकर आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद।' उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि हम जब इसे लेकर बातचीत कर रहे हैं, तभी अहमदाबाद में राष्ट्रपति ट्रंप भी पहुंच चुके हैं। वह 2020 में जिस भारत को देखेंगे, वह उससे बहुत अलग है, जो राष्ट्रपति कार्टर या राष्ट्रपति क्लिंटन या राष्ट्रपति ओबामा ने अपने-अपने दौरों के दौरान देखा है। देश में करोड़ों उपभोक्ता हैं और हर किसी का अपने फोन के साथ निजी अनुभव है। मैं कह सकता हूं कि भारत में मोबाइल नेटवर्क दुनिया के अन्य देशों से बेहतर या समान है और यह बड़ा बदलाव है।'

गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में बुनियादी ढांचा दुनिया में किसी भी जगह से बेहतर है और यह 2020 का भारत है। उन्होंने कहा, 'जब आप 1992 में माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ रहे थे, तब भारत की अर्थव्यवस्था 300 अरब डॉलर थी और आज यह तीन लाख करोड़ डॉलर है। यह पूरी प्रगति तकनीक की बदौलत हुई है।'

यह बदलाव 2014 में उस समय और तेज हो गया, जब प्रधानमंत्री ने देश को डिजिटल इंडिया का नजरिया दिया। अंबानी ने कहा कि वह अपनी दूरसंचार कंपनी जियो शुरू कर इसमें एक छोटी भूमिका अदा करने के लिए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मैं बताना चाहता हूं कि जियो के शुरू होने से पहले भारत में ब्रॉडबैंड की स्पीड 256 केबीपीएस होती थी, लेकिन जियो के आने के बाद भारत के हर गांव में डेटा की औसत स्पीड 21 एमबीपीएस है। जियो के आने से पहले डेटा की कीमत 300 से 500 रुपये प्रति जीबी थी और गरीबों के लिए यह और भी महंगा था।जियो के बाद यह कीमत महज 12 से 14 रुपये प्रति जीबी पर आ गई है। जियो की पिछले तीन साल की उपलब्धि यह है कि 38 करोड़ ग्राहकों ने 4जी तकनीक को अपनाया है।'

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला (दाएं) और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी 24 फरवरी 2020 को मुंबई में माइक्रोसॉफ्ट मुंबई सीईओ समिट के दौरान। *फोटोः कमलेश पेडणेकर*

नडेला ने अंबानी से पूछा कि छोटे, मझोले और बड़े कारोबारों के लिए कुछ करने को लेकर क्या महत्त्वाकांक्षा रखते हैं? इस पर अंबानी ने कहा, 'मैं कहना चाहता हूं कि पांच दशक पहले रिलायंस की स्थापना एक स्टार्टअप के रूप में हुई थी, जिसके पास एक मेज, एक कुर्सी और 1,000 रुपये थे। इसके बाद यह सूक्ष्म इकाई बनी। उसके बाद लघु एवं मझोली और आज आप हमें बड़ी कंपनी के रूप में गिन सकते हैं। यह फिर से मेरी खुशकिस्मती है कि मैं स्टीव (बाल्मर) और बिल गेट्स को स्टैनफर्ड के दिनों से जानता हूं। उस समय बिल स्टीव की नियुक्ति कर रहे थे और मैंने तब से माइक्रोसॉफ्ट की रफ्तार देखी है। भारत में हर छोटे कारोबार और उद्यमी के पास धीरूभाई अंबानी या बिल गेट्स बनने की संभावनाएं हैं। यही चीज भारत को देश दुनिया से अलग करती है। हमारी जड़ों में उद्यमिता शक्ति अथाह है।'

नडेला ने पूछा अंबानी से पूछा कि उनके पिता ने एक सपना लेकर कारोबारी सफर की शुरुआत की और एक बड़ा समूह खड़ा किया, जिसकी अगुआई आज वह कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें किस चीज से प्रेरणा मिलती है और वह क्या देखना चाहेंगे।

अंबानी ने कहा, 'मेरा मानना है कि भारत के पास विश्व में अहम डिजिटल देश बनने की संभावना है। इसे लेकर मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम विश्व की सबसे बड़ी तीन अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होंगे।' 'क्या हम तकनीक के इस्तेमाल के लिहाज से मार्गदर्शक बन सकते हैं।' अंबानी के मुताबिक आगामी दो दशकों में भारत की अगली पीढ़ियां एक अलग भारत पाएंगी।

जापानी कंपनी चेन्नई में लगाएगी संयंत्र

वाहन और गैर-वाहन उत्पादों के इंजन कलपुर्जों की विनिर्माता यूएसयूआई सुसिरा चेन्नई स्थित महिंद्रा लाइफस्पेस की वाणिज्यिक और आवासीय परियोजना-ऑरिजिन्स में नए संयंत्र की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस संयंत्र की स्थापना महिंद्रा वर्ल्ड सिटी द्वारा की जाएगी जो महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स व सुमितोमो कॉरपोरेशन का संयुक्त उद्यम है। *भाषा*

आईएचएच का हिस्सा लेगी अपोलो हॉस्पिटल्स

गिरीश बाबू
चेन्नई, 24 फरवरी

अपोलो हॉस्पिटल्स के प्रबंधन ने कहा है कि कंपनी कोलकाता के अपने अस्पताल अपोलो ग्लेनईगल्स में अपनी मलेशियाई साझेदार आईएचएच हेल्थकेयर बेरहद से उसकी हिस्सेदारी खरीदना चाहती है। कंपनी बेंगलूरु और मुंबई में अपने कारोबार को मजबूत करने के साथ-साथ बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अधिग्रहण की भी संभावनाएं तलाश रही है। इसके अलावा कंपनी अपने पुराने अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और नए अस्पतालों के निर्माण की भी योजना बना रही है।

कोलकाता का अपोलो ग्लेनईगल्स अपोलो हॉस्पिटल्स और आईएचएच की इकाई पार्कवे ग्रुप का बराबर हिस्सेदारी वाला संयुक्त उद्यम है। इस संयुक्त उद्यम साझेदार से हिस्सेदारी खरीदने की पहल ऐसे समय में की गई है जब आईएचएच विभिन्न अस्पतालों के अधिग्रहण के जरिये देश में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। इसी क्रम में उसने फोर्टिस हेल्थकेयर में बहुलांश हिस्सेदारी का भी अधिग्रहण किया था। वर्ष 2018 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में आईएचएच के अस्पतालों की संख्या 33 है और उसके बिस्तरों की संख्या 4,845 है।

अपोलो हॉस्पिटल्स की प्रबंध निदेशक सुनीता रेड्डी ने कहा, 'हम उस संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं। हमें लगता है कि कोलकाता में काफी क्षमता मौजूद है और उस बाजार में अपोलो ब्रांड काफी मजबूत है।' कंपनी सूत्रों ने इससे पहले कहा था कि हिस्सेदारी के मूल्य और कानूनी मुद्दों पर साझेदार के साथ बातचीत चल रही है।

अपोलो हॉस्पिटल्स में आईएचएच की करीब 10 फीसदी हिस्सेदारी थी और 2016 में उसने 6 फीसदी एवं मई 2017 में शेष हिस्सेदारी बेचकर कंपनी से बाहर हो गई थी क्योंकि उसने विभिन्न अस्पताल कंपनियों में हिस्सेदारी के अधिग्रहण के जरिये अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना बनाई थी।

अपोलो ग्लेनईगल्स कोलकाता में अपोलो हॉस्पिटल्स और आईएचएच की इकाई पार्कवे ग्रुप का बराबर हिस्सेदारी वाला संयुक्त उद्यम है

अपोलो हॉस्पिटल्स को बेंगलूरु, कोलकाता और मुंबई में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का भी अवसर रहा है जबकि निकट भविष्य में उसके नए विस्तरों के परिचालन में आने की उम्मीद है। कंपनी ने कुछ वर्ष पहले उल्लेखनीय निवेश के साथ इन बिस्तरों का निर्माण शुरू किया था। इन शहरों में मौजूद अवसरों को देखते हुए कंपनी अधिग्रहण के मोर्चे पर भी आगे बढ़ सकती है जिसकी जरूरत तीन साल बाद हो सकती है। अपोलो हॉस्पिटल्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी कृष्णन अखिलेश्वरन ने कहा कि कंपनी को इस प्रकार के अधिग्रहण का फायदा वित्त वर्ष 2024 तक मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे कंपनी की बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ेगी।

रेड्डी ने कहा कंपनी अगले वित्त वर्ष के दौरान 250 से 300 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च की उम्मीद कर रही है जबकि कोलकाका के संयुक्त उद्यम जैसा कोई अन्य अधिग्रहण इस योजना से अलग होगा। कंपनी कुछ बाजारों में अग्रणी होना चाहती है और अपने नकदी प्रवाह के बल पर वह ऐसा कर सकती है। उन्होंने कहा कि अपोलो हॉस्पिटल्स ने चेन्नई, हैदराबाद, विशखापत्तनम और काकीनाडा आदि शहरों में नए बिस्तरों को परिचालन में शामिल करने की योजना बनाई है।

एयर इंडिया की दौड़ में अदाणी

ड्यू डिलिजेंस यानी जांच-परख पर निर्भर होगा अदाणी का अंतिम फैसला

अनीश फडणीस और देव चटर्जी
मुंबई, 24 फरवरी

एयर इंडिया के अधिग्रहण की दौड़ में अदाणी समूह शामिल हो गया है और उसकी योजना अगले महीने अभिरुचि पत्र जमा कराने की है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी।

इस पर अंतिम फैसला हालांकि अभिरुचि पत्र जमा कराए जाने के बाद ड्यू डिलिजेंस यानी जांच परख पर निर्भर होगा। अभिरुचि पत्र जमा कराए जाने से अदाणी समूह को संभावित बोलीदाताओं के डेटा रूम तक पहुंच मिल जाएगी। अदाणी समूह के अलावा टाटा समूह, हिंदुजा समूह, इंडिगो एयरलाइन और न्यू यॉर्क की फंड इंटरप्स इसके लिए अभिरुचि पत्र जमा करा सकते हैं।

अदाणी समूह की महत्वाकांक्षा भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऑपरेटर के तौर पर उभरने की है और उसकी झोली में तीन हवाईअड्डे लखनऊ, अहमदाबाद और मंगलूरु हैं। कंपनी तीन अन्य हवाईअड्डों तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद और गुवाहाटी के लिए सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है।

इस बारे में अदाणी समूह के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। विश्लेषकों का हालांकि मानना है कि हवाईअड्डों के स्वामित्व के कारण एयर इंडिया के लिए समूह की बोली कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकती है। एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की खातिर किसी एयरपोर्ट डेवलपर पर हालांकि पाबंदी नहीं है, लेकिन अदाणी समूह को मिले एयरपोर्ट अथॉरिटी के छह हवाईअड्डों की बोली की शर्तों में स्वामित्व की सीमा है।

बोली के मानकों के मुताबिक, कोई विमानन कंपनी या समूह (विमानन के स्वामित्व वाला) इन छह हवाईअड्डों में 27 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं ले सकता और यह समूह के लिए मामला जटिल बना सकता है। किसी विमानन कंपनी या समूह के लिए दिल्ली एयरपोर्ट की 10 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी सीमा से हाल में जीएमआर में टाटा-जीआईसी समूह का निवेश नहीं हो पाया।

एयर इंडिया की बिक्री प्रक्रिया से जुड़े एक बैंकर ने कहा, मौजूदा नियम अदाणी समूह को एयरलाइंस के लिए बोली लगाने से नहीं रोकेगा। सूत्र ने कहा, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी बोली लगाए क्योंकि कंपनी का 30,000 करोड़ रुपये का कर्ज अलग किए जाने और सरकार की तरफ से 100 फीसदी हिस्सेदारी की पेशकश उसे अच्छी परिसंपत्ति बनाता है।

विमानन कंपनी बेचने की यह सरकार की दूसरी कोशिश है जब पिछले साल पहले दौर में उसे कोई भी खरीदार नहीं मिला। तब सरकार ने कंपनी की 76 फीसदी के बजाय 100 फीसदी हिस्सेदारी की पेशकश की।

एयर इंडिया और उसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस के करीब 120 विमान वित्त वर्ष 2018 के आखिर में थे जबकि पिछले साल सितंबर तक 126 विमान थे।

निजी कंपनी को एयर इंडिया की बिक्री सरकार के लिए अहम है क्योंकि साल 2012 से सरकार को इस कंपनी में 30,000 करोड़ रुपये झोंकने पड़े हैं। विमानन कंपनी को हालांकि साल 2007 में एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस के विलय का फायदा नहीं मिला है।

अदाणी समूह की रुचि

- अदाणी समूह की महत्वाकांक्षा भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऑपरेटर के तौर पर उभरने की है और उसकी झोली में तीन हवाईअड्डे लखनऊ, अहमदाबाद और मंगलूरु हैं
- हालांकि हवाईअड्डों के स्वामित्व के कारण एयर इंडिया के लिए समूह की बोली कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकती है

कोरोनावायरस से टीवीएस के उत्पादन पर 10 फीसदी असर

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 24 फरवरी

टीवीएस मोटर ने कहा है कि चीन में कोरोनावायरस फैलने से फरवरी में नियोजित उत्पादन में 10 फीसदी की गिरावट आएगी। इससे पहले देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प भी कह चुकी है कि फरवरी में कंपनी का उत्पादन 10 फीसदी प्रभावित होगा।

टीवीएस मोटर ने कहा, कोरोनावायरस के कारण बीएस-6 वाहनों के उत्पादन के लिए कुछ निश्चित कलपुर्जे की आपूर्ति पर असर पड़ा है। वैश्विक ऑटोमोबाइल आपूर्ति श्रृंखला का चीन अहम हिस्सा है।

कंपनी ने कहा, हालांकि कलपुर्जे के लिए चीन पर हमारी प्रत्यक्ष निर्भरता सीमित है, लेकिन कुछ टियर-2 आपूर्तिकर्ताओं पर प्रतिकूल असर पड़ा है, जिससे फरवरी 2020 में नियोजित उत्पादन में 10 फीसदी की कमी आएगी। कंपनी ने कहा, स्थिति को सामान्य करने के लिए हर तरह की कोशिशें जारी हैं। टीवीएस मोटर कंपनी के निदेशक व सीईओ केएन राधाकृष्णन ने कहा, जनवरी 2020 से हम पूरी तरह बीएस-6 की ओर जा चुके हैं। बीएस-6 वाहनों के उत्पादन पर असर को न्यूनतम करने के लिए हम आपूर्ति करने वालों के साथ हो रही प्रगति पर निगरानी रखे हुए हैं, जो चीन से कुछ निश्चित कलपुर्जे का आयात करते हैं। इसके साथ ही हम अन्य क्षेत्रों से आपूर्ति की संभावना तलाश रहे हैं और भारत के भीतर इसके स्थानीयकरण पर विचार कर रहे हैं। उपभोक्ता केंद्रित संगठन होने के नाते हमारी कोशिश यह सुनिश्चित करने की है कि हमारे ग्राहकों और परिचालन पर असर न्यूनतम हो। चीन में कोरोनावायरस के प्रसार से कुछ वाहन निर्माताओं का उत्पादन प्रभावित हुआ है जबकि अन्य ने कहा कि उनके पास एक महीने के उत्पादन के लिए पर्याप्त इंतजाम है। उन्होंने कहा, अगर अगले एक महीने में फैक्टरियां नहीं खुलती हैं तो हमारे सामने वास्तविक चुनौती होगी। सकारात्मक पहलू यह है कि वैश्विक स्तर पर जिंस की कीमतों में संभावित गिरावट के कारण चीन बैटरी व टायर फर्मों मसलन अपोलो टायर के मार्जिन को सहारा दे सकता है। क्रिसिल के अनुमान के मुताबिक, आयातित वाहन कलपुर्जे का करीब 18 फीसदी और करीब 30 फीसदी टायरों का आयात चीन से होता है। भारतीय वाहन कलपुर्जा विनिर्माता संगठन ने कहा कि भारत ने साल 2019 में चीन से करीब 4.2 अरब डॉलर के वाहन कलपुर्जे का आयात किया।

चीन गके ने वर्ष के अनुमान से कंपनियों ने इन्वेंट्री का स्टॉक बना लिया था। ऐसे में वायरस के प्रकोप से वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में सीमित अवरोध हो सकता है क्योंकि भारतीय ओईएम 30 से 60 दिन की इन्वेंट्री का आयात करते हैं।

क्रिसिल के विश्लेषक ने कहा है, लेकिन अहम कलपुर्जे मसलन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का अभाव ओईएम की वाहन विनिर्माण की क्षमता पर असर डाल सकता है। मौजूदा मंदी और बीएस-6 वाहनों का पर्याप्त स्टॉक देसी ओईएम को राहत दे रहा है, हालांकि उत्पादित बीएस-6 वाहनों की बिक्री 1 अप्रैल 2020 से अनिवार्य होगी।

कोरोना से आया बाजार को रोना

पृष्ठ-1 का शेष

निवेशकों के बीच बढ़ती चिंताओं पर वैलेंटिस एडवाइजर्स के संस्थापक ज्योतिवर्द्धन जयपुरिया ने कहा, 'लोग वायरस के तेजी से फैलने से परेशान दिख रहे हैं। हालात ऐसे ही रहें तो वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को और चोट पहुंच सकती है।' विश्लेषकों का कहना है कि यूरोप में कोरोनावायरस के पहुंचने से निवेशकों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। पहले उन्हें लग रहा था कि यह संक्रमण केवल एशिया तकक ही सीमित है। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट के संस्थापक सौरभ मुखर्जी ने कहा, 'कोरोनावायरस चीन से शुरू होकर अब इटली तक पहुंच गया है। अगर स्थिति अगले तीन महीनों तक जारी रही तो पूरी दुनिया में आपूर्ति प्रभावित होगी और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। वाहन, बिजली एवं दवा उद्योग पर सबसे अधिक मार पड़ सकती है।'

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्रमुख (खुदरा शोध) दीपक जसानी ने कहा कि स्थिति में सुधार के बहुत अधिक संकेत नहीं मिलने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दीर्घ अवधि तक इसका असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है।

दसॉ सिस्टम्स ने दीपक को बनाया भारत में एमडी

सॉफ्टवेयर कंपनी दसॉ सिस्टम्स ने दीपक एनजी को भारतीय कारोबार का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यह दसॉ समूह की इकाई है। दीपक के पास विभिन्न उद्योगों का 21 साल का अनुभव है। दसॉ सिस्टम्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष सैमसन खाओ ने कहा, भारत एशिया में हमारे के लिए सबसे प्राथमिकता वाले बाजारों में है।

25 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है डीएचएफएल घोटाला

पृष्ठ-1 का शेष

येस बैंक के साथ वित्तीय संबंधों के बारे में ईडी की जांच में कहा गया है कि बैंक का डीएचएफएल डिबेंचर में अप्रैल 2018 और जून 2018 के बीच 3,700 करोड़ रुपये का कर्ज था। इसके अलावा येस बैंक ने धीरज वधावन की कंपनी आरकेडब्ल्यू डेवलपर को मुंबई के करीब बांदा में एक परियोजना के लिए 750 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया था।

येस बैंक ने इस बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि बैंक की निजता नीति के तहत ग्राहक की जानकारी और उससे संबंधित लेनदेन का का खुलासा नहीं किया जा सकता है। एक मैसेज में राणा कपूर ने कहा कि आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं।

ईडी अंडरवर्ल्ड सरगना इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची को पैसे देने के मामले में डीएचएफएल के प्रवर्तकों की भूमिका की जांच कर रहा है। एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि अब कंपनी के हरेक वित्तीय लेनदेन की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है।

'विवाद से विश्वास' नहीं देगा एमएनसी को राहत

हस्तांतरण मूल्य निर्धारण संबंधी अपने विवादों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पूरे विवादित धन को भारत में लाना होगा

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 24 फरवरी

9.32 लाख करोड़ रुपये पर नजर

मद	अनुमान#	संग्रह*	अंतर**
कॉर्पोरेशन कर	6,10,500	3,69,553	2,40,967
व्यक्तिगत आयकर	5,59,500	3,17,652	2,41,848
कुल	11,70,000	6,87,185	4,82,815

2019-20 का संशोधित अनुमान
**3 महीनों में भरा जाना है यह अंतर
*दिसंबर तक वास्तविक संग्रह
आंकड़े करोड़ रुपये में
स्रोत : बजट, लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय

बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) की सहायक कंपनियां प्रस्तावित योजना 'विवाद से विश्वास' के तहत हस्तांतरण मूल्य निर्धारण संबंधी अपने विवादों का निपटारा तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें पूरे विवादित धन को भारत में लाना होगा। और अगर यह पैसा भारत में नहीं लाया जाता है तो, इसे सहायक कंपनियों से मुख्यालय को दिए गए कर्ज के रूप में माना जाएगा जिस पर ब्याज देना होता है।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक के संशोधन, जिसे हाल ही में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, का कहना है कि स्थानांतरण मूल्य निर्धारण से संबंधित विवाद निपटान वाले संशोधन का दूसरे संशोधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आइए इस अवधारणा को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की एक भारतीय सहायक कंपनी अपने वैश्विक मुख्यालय को कुछ तकनीकी सेवा प्रदान करती है। अपने बहीखाते में वह दिखाती है कि मुख्यालय द्वारा उसे 100 करोड़ रुपये दिए गए थे और वह इस पर कर का भुगतान करती है। हालांकि स्थानांतरण मूल्य निर्धारण करने वाले अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रदान की गई सेवा 110 करोड़ रुपये की थी और उस सहायक कंपनी को 110 करोड़ रुपये का कर देना होगा। अब यह मतभेद किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल में जा सकता है।

इस विवाद को 110 करोड़ रुपये का कर चुकाकर निपटाया जा सकता है, लेकिन 110 करोड़ रुपये की यह पूरी राशि भारत में लानी होगी। वरना इसे बहुराष्ट्रीय कंपनी को इसकी सहायक कंपनी द्वारा 110 करोड़ रुपये के कर्ज के रूप में माना जाएगा और इस पर प्रति वर्ष छह प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। वैकल्पिक रूप से इस पर 18 प्रतिशत का पूर्णकालिक ब्याज और 12 प्रतिशत का अधिभार यानी दूसरे शब्दों में कुल 110 करोड़ रुपये का 20.16 प्रतिशत भुगतान करके मामला सुलझाया जा सकता है।

अशोक माहेश्वरी ऐंड एसोसिएट्स के साझेदार अमित माहेश्वरी का कहना है कि इस तरह, घोषणा करने वाले व्यक्ति को यह धनराशि वापस भारत लानी होगी, भले ही वह इस योजना के तहत निपटान का ही रास्ता क्यों न चुने। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इसके पीछे इरादा केवल मुकदमेबाजी के लिए राहत देने का है, धन की वापसी में राहत देने का नहीं।

यह योजना 31 जनवरी, 2020 तक आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित इन विवादों के निपटारे के लिए ब्याज, जुर्माने और अभियोजन की छूट प्रदान करती है।

हालांकि 31 मार्च तक किए गए भुगतान के मामले में ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट दी जाएगी तथा इसके बाद इस विवादित राशि का दस प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा।

केवल विवादित ब्याज या जुर्माना से संबंधित कर बकाया मामले में 31 मार्च, 2020 तक अपील का निपटारा करते समय विवादित जुर्माने या ब्याज के 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा और अगर इस तारीख के बाद भुगतान किया जाता है तो 30 प्रतिशत भुगतान करना होगा।

टीसीएस, डीएलएफ ने सेज पर मांगी सरकार से मंजूरी

भाषा
नई दिल्ली, 24 फरवरी

सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस और जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी डीएलएफ ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) गठित करने को लेकर सरकार से मंजूरी मांगी है।

सरकार से मांगी मंजूरी

इन प्रस्तावों पर सेज के लिए निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय मंजूरी बोर्ड विचार करेगा। बोर्ड की बैठक यहां 26 फरवरी को होगी। अंतर मंत्रालयी निकाय की अध्यक्षता वाणिज्य सचिव करते हैं।

बोर्ड बैठक के एजेंडा पत्र के अनुसार टीसीएस ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में 19.9 हेक्टेयर क्षेत्र में आईटी और आईटी संबद्ध सेज के गठन का प्रस्ताव किया है। परियोजना में कुल प्रस्तावित निवेश 2,433.72 करोड़ रुपये है। नोएडा सेज के विकास आयुक्त ने सेज स्थापित करने को लेकर औपचारिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है।

वहीं डीएलएफ ने हरियाणा में दो सेज के गठन का प्रस्ताव किया है। इन दोनों परियोजनाओं में क्रमश: 793.95 करोड़ रुपये और 761.54 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इन दोनों कंपनियों के अनुरोधों को विचार के लिए मंजूरी बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। देश में सेज प्रमुख निर्यात केंद्र है। सरकार इन्हें कई प्रोत्साहन और एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली उपलब्ध कराती है।

सरकार ने 14 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार 417 सेज के गठन को मंजूरी दी है। इसमें से 238 क्षेत्र परिचालन में हैं। इन क्षेत्रों से निर्यात 2019-20 की अप्रैल-सितंबर अवधि में करीब 14.5 प्रतिशत बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये रहा। पूरे वित्त वर्ष 2018-19 में यह 7.02 लाख करोड़ रुपये था।

सीएए प्रदर्शन उग्र, सिपाही की मौत

बीएस संवाददाता/भाषा
नई दिल्ली, 24 फरवरी

- **जाफराबाद व मौजपुर इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग, एक पुलिसकर्मी की मौत, अधिकारी घायल**
- **कई मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश व निकास बंद किया गया**
- **एलजी का दिल्ली पुलिस आयुक्त को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश**
- **दिल्ली सरकार की दिल्ली वासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील**

दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध-समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों से सोमवार को हालात बिगड़ गए। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद और मौजपुर इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने कम से कम दो घरों में आग लगा दी। प्रदर्शन के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई। जिससे तनाव और बढ़ गया है। इन इलाकों में सोमवार को लगातार दूसरे दिन सीएए समर्थक और विरोधी समूहों के बीच झड़पें हुईं। प्रदर्शनकारियों ने एक-दूसरे पर पथराव किया। तनाव बढ़ने के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा,' मैंने अभी एलजी साहिब से बात। उन्होंने भरोसा दिलाया कि और पुलिस बल भेजी जा रही है। किसी के भी द्वारा हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरी सभी लोगों से विनती है कि कृपया शांति बनाए रखें। हिंसा से काई समाधान नहीं निकलेगा'। केजरीवाल ने कहा कि पुलिस हेड कांस्टेबल की मौत बेहद दु:खदायी है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व अन्य मंत्रियों ने दिल्लीवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने समूहों को शांत कराने के भी प्रयास किए। अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने इलाके में लगी आग बुझाते समय दमकल की एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया।

दिल्ली मेट्रो ने इलाके में तनाव के बीच जाफराबाद और मौजपुर-बाबरपुर सहित कई स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए। इन स्टेशनों पर ट्रेनें नहीं रुकेंगी। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार पिछले 24 घंटों से बंद हैं।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रविवार को सड़क अवरुद्ध कर दी थी जिसके बाद जाफराबाद में सीएए के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प शुरू हो गई थी। दिल्ली के कई अन्य इलाकों में भी ऐसे ही धरने शुरू हो गए हैं। मौजपुर में भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने एक सभा बुलाई थी जिसमें मांग की गई थी कि पुलिस तीन दिन के भीतर सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को हटाए, इसके तुरंत बाद दो समूहों के सदस्यों ने एक-दूसरे पर पथराव किया, जिसके चलते पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

भविष्य में बैंकों के हो सकते हैं अलग-अलग क्षेत्र

अनूप रॉय
मुंबई, 24 फरवरी

> पहली श्रेणी में घरेलू व अंतरराष्ट्रीय श्रेणी के बड़े बैंक, दूसरी श्रेणी में मझोले बैंक और तीसरी श्रेणी में निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चौथी श्रेणी में डिजिटल क्षेत्र हो सकता है

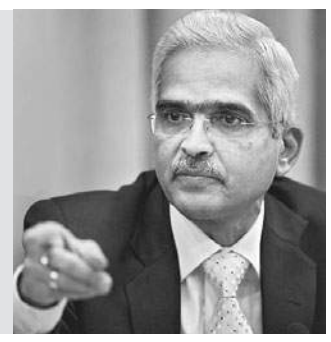

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि भविष्य के बैंक इस समय के बैंकों से बिल्कुल अलग होंगे और इन अलग क्षेत्र के बैंकों का नियमन करना नियामक के लिए चुनौतीपूर्ण काम होगा।

आर्थिक समाचार पत्र मिंट के सालाना बैंकिंग कार्यक्रम में दास ने कहा कि ऐसी स्थिति में भारत में काम करने वाली वित्तीय फर्मों के समाधान के लिए निकट भविष्य में एकीकृत ढांचे की उम्मीद की जा सकती है, जिससे वित्तीय व्यवस्था में लचीलापन आ सके।

इस समय फाइनैंशियल टेक्नोलॉजी कंपनयां मौजूदा बैंकों के सामने चुनौतियां पेश कर रही हैं, लेकिन तमाम बड़ी तकनीकी कंपनियां या बिगटेक्स हैं, जो वित्तीय सेवा उद्योग में व्यापक रूप से प्रवेश कर रही हैं। कुछ बिगटेक्स अपने डेटा नेटवर्क गतिविधियों पर निर्भर हैं, वहीं कुछ पेमेंट्स, धन प्रबंधन, बीमा और कर्ज देने की गतिविधियों में संयुक्त उद्यम बना रही हैं।

दास ने कहा, 'इस समय वित्तीय सेवाएं उनके वैश्विक कारोबार का छोटा हिस्सा हैं। लेकिन उनके आकार और पहुंच को देखते हुए वित्तीय सेवा में उनके प्रवेश से वित्तीय क्षेत्र में तेज बदलाव लाने की क्षमता है। इन फर्मों के प्रवेश से तमाम लाभों की संभावना है और वे कम लागत पर बड़ी संख्या में लोगों को बुनियादी वित्तीय सेवाएं मुहैया करा सकती हैं।'

लेकिन फिनटेक और बिगटेक्स का आगमन बैंकों और इसके साथ ही बैंकिंग नियामक के लिए चुनौती है। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए बैंक नई तकनीक और कारोबार को अपना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग नियामक नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने और उसी अनुपात में निरीक्षण व नियामकीय ढांचा बनाने में संतुलन स्थापित करने में लगे हैं।

दास ने अपने भाषण में कहा, 'इसका मतलब यह है कि बैंकिंग का भविष्य पिछली व्यवस्था की निरंतरता नहीं रहने जा रही है। ढांचे और कारोबारी मॉडल के हिसाब से आगामी वर्षों में हम बहुत अलग तरह का बैंकिंग सेक्टर देखेंगे।'

बैंकों की अलग अलग श्रेणियां हो सकती हैं। पहली श्रेणी बड़े भारतीय बैंकों की हो सकती है, जिनकी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी होगी, जिसके लिए सरकारी क्षेत्रों के विलय की प्रक्रिया पहले से चल रही है।

दूसरे सेग्मेंट में मझोले आकार के बैंक और तीसरे सेग्मेंट में छोटे निजी क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक हो सकते हैं। चौथी श्रेणी डिजिटल प्लेयर्स की हो सकती है, जो सीधे ग्राहकों के सेवा प्रदाता के रूप में या बैंकों के माध्यम से उनके एजेंट या सहयोगी के रूप में काम कर सकते हैं।

हर स्थिति में परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था नई पीढ़ी की बैंकिंग के लिए राह बनाएगी, जिसमें डिजिटलीकरण व आधुनिकीकरण पर ध्यान होगा, जिसमें परंपरागत बैंक शाखाओं की लगातार समीक्षा की जरूरत होगी।

गवर्नर ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) जल्द ही एक सहायक इकाई स्थापित करने पर फैसला करेगा, जिसका ध्यान अन्य देशों के लिए यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) मॉडल पर होगा, जो भारत की भुगतान व्यवस्था की वैश्विक पहुंच बढ़ाएगा। खुदरा भुगतान के लिए एक नई इकाई से प्रतिस्पर्धा बढ़े गी और खुदरा भुगतान क्षेत्र में आगे और नवोन्मेष होगा, जिसके लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

रिजर्व बैंक के गवर्नर के मुताबिक इंपेयर्ड एसेट में कमी और प्रॉविजनिंग में उल्लेखनीय सुधार के बावजूद बैंकिंग क्षेत्र के मुनाफे की स्थिति नाजुक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पूंजीकरण में सुधार हुआ है, लेकिन दूरसंचार जैसे क्षेत्रों से लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं।

उन्होंने कहा, 'इसकी वजह से गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) उच्च स्तर पर बनी हुई है और कर्ज की वृद्धि दर प्रभावित हो रही है।' बैंकों ने अपना ध्यान बड़े बुनियादी ढांचा क्षेत्र और औद्योगिक कर्ज से अपना ध्यान हटाकर खुदरा कर्ज पर केंद्रित कर दिया है, लेकिन विविधीकरण की इस रणनीति की अपनी सीमाएं हैं।

मंदी के बीच 15 प्रतिशत तक ब्याज भुगतान कर रही हैं रियल एस्टेट फर्में

राघवेंद्र कामत और अभिजित लेले
मुंबई, 24 फरवरी

दोहरी मार

- **डेवलपरों को 13.5 प्रतिशत से 14.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है। यह दो साल पहले 10 से 12 प्रतिशत था**
- **बैंक रियल एस्टेट क्षेत्र को कर्ज देने में 30 से 45 दिन लगाते थे। इस समय 90 से 120 दिन लग रहे हैं**
- **कुछ डेवलपरों के मुताबिक आवासीय परियोजनाओं के लिए बैंक उधार नहीं दे रहे हैं और एनबीएफसी की अपनी चुनौतियां**
- **हालांकि ब्रांड बन चुके डेवलपरों का कहना है कि उन्हें आसानी से और पहले से सस्ता कर्ज मिल रहा है बाजार में सस्ते मकानों की बनी हुई है मांग**

लंबे समय से बिक्री में सुस्ती झेल रहे रियल एस्टेट डेवलपरों को संपत्तियों के निर्माण के लिए धन के संकट से जूझना पड़ रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में डेवलपरों ने कहा कि जिन्हें फंड मिल रहा है, उन्हें बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है।

2018 में इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) के संकट के बाद से उपजे नकदी के संकट के बाद डेवलपरों के लिए निर्माण के लिए धन जुटाना मुश्किल हो गया है, जिसे एक समय में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और बैंक सबसे सुरक्षित उधारी मान रहे थे।

जिन्हें निर्माण के लिए धन मिल रहा है, उन्हें 13.5 प्रतिशत से 14.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है। यह दो साल पहले 10 से 12 प्रतिशत था।

मैराथन रियल्टी के प्रबंध निदेशक मयूर शाह ने कहा, 'बेहतरीन कंपनियों के लिए भी कंस्ट्रक्शन फाइनैंस मुश्किल हो गया है. यहां तक कि सरकारी बैंक भी 13.5 प्रतिशत ब्याज ले रहे हैं।'

डेवलपरों के मुताबिक एसबीआई कैप वेंचर्स द्वारा डेवलपरों को उधारी देने के लिए बनाए गए 25,000 करोड़ रुपये के डिस्ट्रेस एसेट फंड से 15 प्रतिशत ब्याज पर धन मिल रहा है।

बहरहाल एसबीआईकैप वेंचर्स के स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड 1 के मुख्य निवेश अधिकारी इरफान ए काजी का कहना है कि अन्य कर्जदाताओं से इतर फंड मैनेजर परियोजना पूरी होने तक ब्याज नहीं लेते।

शाह ने कहा, 'पिछले 18 महीने में भारतीय रिजर्व बैंक ने दरों में कई बार कटौती की, लेकिन डेवलपरों के लिए उधारी दर बढ़ती ही जा रही है।'

मुंबई की अजमेरा रियल्टी के निदेशक धवल अजमेरा ने कहा कि मानकों के पालन को लेकर बैंक बहुत सख्त हैं और कर्ज देने की रफ्तार बहुत सुस्त हो गई है। उन्होंने कहा, 'इसके पहले वे कर्ज देने में 30 से 45 दिन लगाते थे। अब इस समय 90 से 120 दिन लग रहे हैं।'

मुंबई के एक अन्य प्रमुख डेवलपर ने नाम न देने की शर्त पर कहा कि बैंक जोखिम लेने को तैयार नहीं हैं और एनबीएफसी के पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'यहां तक कि लीज रेंटल डिस्काउंटिंग (एलआरडी) दरें भी बढ़ गई हैं। एलआरडी बैंकरों के लिए सबसे सुरक्षित कर्ज है।' डेवलपर ने कहा कि मुंबई की एक एनबीएफसी डेवलपरों से तिमाही ब्याज ले रही है, लेकिन उसने कंस्ट्रक्शन फाइनैंस जारी करने की पहले की प्रतिबद्धता पूरी करने से इनकार कर दिया है।

बेंगलूरु की डेवलपर द ओजोन ग्रुप के मुख्य कार्यकारी श्रीनिवासन गोपालन ने कहा कि कोई कर्ज उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा, 'आवासीय परियोजनाओं के लिए बैंक उधार नहीं दे रहे हैं और एनबीएफसी की अपनी चुनौतियां हैं।'

गोपालन ने कहा कि ओजोन ज्यादातर ग्राहकों से धन जुटाने की कवायद कर रही है और अपनी परियोजनाओं की आक्रामक रूप से मार्केटिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि बेंगलूरु और चेन्नई में सस्ते आवास के क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है।

निवेश सलाहकार मोनल कैपिटल में चेयरमैन अजय जैन ने कहा, 'कार्यशील पूंजी की उपलब्धता के लिए डेवलपरों को अपनी ही कंपनी से उधारी और विभिन्न परियोजनाओं पर निर्भर रहना पड़ रहा है। बहरहाल कछ शीर्ष प्रॉपर्टी डेवलपरों का कहना है कि उनके ऊपर बहुत असर नहीं पड़ा है।'

गोदरेज प्रॉपर्टीज के एक प्रवक्ता ने कहा, 'हमारी मौजूदा औसत उधारी दर 8 प्रतिशत है, जो पिछले साल की उधारी दर के कमोबेश बराबर है। हमें कंस्ट्रक्शन फाइनैंस जुटाने में कोई दिक्कत नहीं है।'

ओबेरॉय रियल्टी के एक अधिकारी ने कहा कि न तो ओबेरॉय न ही किसी अन्य प्रतिष्ठित कंपनी को बैंकों से धन पाने में कोई दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा, 'इस उद्योग में हमारी उधारी लागत सबसे कम है। यह बढ़ी नहीं है, बल्कि कम हुई है।'

बहरहाल बैंकरों का कहना है कि इस क्षेत्र में जोखिम को देखते हुए वे सावधानी बरत रहे हैं। सीएसबी बैंक के मुख्य कार्याधिकारी और प्रबंध निदेशक सीवी राजेंद्रन ने कहा कि मुंबई, दिल्ली और चेन्नई के बाजार के कुछ इलाकों में निर्माण के लिए कर्ज देने में सावधानी बरती जा रही है। उनका बैंक वसूली के कड़े प्रावधान के कारण चुनिंदा कर्ज देने पर ध्यान दे रहा है।

निजी क्षेत्र के एक और बैंकर ने कहा कि चूक की जोखिम को देखते हुए ज्यादा ब्याज दरों से इसकी कुछ सीमा तक भरपाई हो रही है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 8

मतदान का `आधार'

सरकार ऐसा कानून बनाने की तैयारी में है जिसमें विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने वाले आधार क्रमांक को मतदाता पहचान-पत्र से जोड़ने का प्रावधान होगा। इस तरह के फैसले के पीछे की सरकार की मंशा समझना आसान है। तमाम सरकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों का दोहराव रोकने के लिए आधार डेटा का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी स्थिति में अफसरशाही आधार क्रमांक और मतदाता पहचान-पत्र जोड़ने को सरकारी कार्यक्रमों और मतदान के लिए योग्य भारतीयों की एक संपूर्ण सूची तैयार करने की दिशा में सिर्फ अगले कदम के तौर पर देख रही है। लेकिन आधार और मतदाता पहचान-पत्र जोड़ने के कई ऐसे नतीजे भी होंगे जिनका ध्यान रखने की जरूरत है। निश्चित रूप से आधार के उपयोग से एक से दूसरे निर्वाचन-क्षेत्र में जाने वाले मतदाताओं को राहत मिल सकती है। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें आर्थिक एवं अन्य कारणों से अपना गृह-क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। आधार से मतदाता पहचान-पत्र जुड़े होने से वे नई जगह पर भी मतदान आसानी से कर पाएंगे।

हालांकि यहां पर यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि सरकार एक ऐसी चीज को क्यों अनिवार्य बनाना चाहती है जिसे मौलिक रूप से पूरक माना गया था? अगर आधार की संकल्पना एक ऐसे तरीके के तौर पर की गई है जिसके माध्यम से कोई दूसरा पहचान-पत्र नहीं रखने वाला व्यक्ति भी निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष अपनी पहचान साबित कर सकता है तो फिर इसे गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर इसे एक संभावित मतदाता की राह में खड़े होने वाले एक और अवरोध के तौर पर देखा जा रहा है तो फिर अलग बात है। उस स्थिति में मताधिकार का दायरा व्यापक करने का मकसद ही पूरा नहीं होता है। यहां यह प्रश्न केंद्र में आ जाता है कि सरकार नागरिकों के आंकड़े तक क्यों और कैसे पहुंच रख सकती है? अगर नागरिकों के बारे में जुटाए गए आंकड़े तक पहुंच और उपयोग पर नियंत्रण के तरीके तय करने वाला समुचित कानून बन जाता है तो फिर मतदाता खुद को अशक्त या भयभीत नहीं महसूस करेगा। इस संदर्भ में ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग को लेकर चर्चा हुई है। सच तो यह है कि चाहे जिस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा हो, अगर नागरिकों से संबंधित आंकड़े कूटबद्ध रूप में रखे गए हैं तो फिर निश्चित तौर पर आपत्तियां कम होंगी। इसके अलावा ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में आधार के इस्तेमाल को पहले प्रायोगिक स्तर पर परख लेना चाहिए। इसे बेहद सीमित पैमाने पर परखे जाने के पहले एक साथ पूरे देश या एक राज्य में भी नहीं लागू कर देना चाहिए। अभी तक यह साफ हो जाना चाहिए कि आधार के जरिये बड़े पैमाने पर सत्यापन करना भी कोई कम-जटिल कवायद नहीं है। मतदाता सूची में संशोधन जैसे संवेदनशील मामलों को सूची से बाहर किए जा रहे लोगों का ध्यान रखे बगैर आधार प्रक्रिया के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। क्रमिक क्रियान्वयन या प्रायोगिक कार्यक्रमों से पता चल सकता है कि कौन लोग बाहर हो रहे हैं?

अफसरशाह आधार कार्ड के ऐसे उपयोगों के बारे में सुझाव देते रहेंगे जब तक कि सरकार द्वारा जुटाए गए नागरिकों के निजी डेटा के इस्तेमाल को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं बन जाता है। डेटा निजता पर एक समग्र कानून यह काम कर देगा। लेकिन आज के समय में यह एक निरर्थक उम्मीद ही लगती है। लिहाजा नागरिक डेटा के उपयोग के बारे में सरकार की शक्तियां सीमित करने वाले कानून को लाए जाने की संभावना बेहद कम ही है। लेकिन ऐसा होने पर भी सरकार और चुनाव आयोग को सत्यापन के इकलौते जरिये के रूप में आधार कार्ड पर निर्भरता बढ़ने के खतरों को भी समझना होगा।

बिनय सिन्हा

डिजिटल अर्थव्यवस्था पर करारोपण की चुनौतियां

इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सेवाएं देने के ऑनलाइन कारोबार पर करारोपण की राह में कई तरह की चुनौतियां हैं। इन समस्याओं पर विस्तार से रोशनी डाल रहे हैं पार्थसारथि शोम

डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर लगाने का तरीका एक ऐसा मसला है जो अंतरराष्ट्रीय नीति-निर्माताओं की चिंता का विषय बना हुआ है। गत अगस्त में आईटीआरएएफ1 के शोधकर्ताओं ने इस प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कराधान से जुड़ी सीमाओं का जिक्र किया था। कुछ दिन पहले प्रकाशित एक संस्करण में इस रिपोर्ट के नतीजे रखे गए हैं जो अंतरराष्ट्रीय कराधान पर वार्षिक शृंखला का चौथा संस्करण है।

शिखा मेहरा और रोहित रॉय ने ब्लॉकचेन और उसकी कर चुनौतियों के बारे में लिखा है। कंपनी आयकर में लाभ को आधार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि वीवर्क और उबर जैसी बड़ी मूल्य वाली इंटरनेट कंपनियों का आधुनिक कारोबारी मॉडल मुनाफे के बजाय परंपरागत कर नेटवर्क को बाइपास करते हुए वृद्धि-केंद्रित मॉडल की तरफ खिसकता जा रहा है। इसके जवाब में कर-आधारित क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) से निपटने के लिए आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी), संयुक्त राष्ट्र और देशों के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

ओईसीडी की अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक, वेब 2.0 के दौर में तकनीकी प्रगति ने फेसबुक, उबर और एमेजॉन जैसे डेटा एग्रीगेटरों पर सक्रिय कंपनियों के मुनाफे में खासी बढ़ोतरी की है। इसके उलट डेटा के मौलिक यानी उपयोगकर्ताओं को शायद ही कोई आय होती है। इसके अलावा इन कंपनियों की उन देशों में मौजूदगी बहुत कम या नदारद है जहां से ये डेटा जुटाती हैं।

इसके उलट वेब 3.0 तकनीक उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा का स्वामित्व देती है और वे इस डेटा को इन कंपनियों को बेचकर कमाई कर सकते हैं। अगर इसे लागू किया जाए तो इससे कर क्षेत्राधिकार तय हो सकेगा जहां से उपयोगकर्ता-जनित डेटा जुटाया गया है ताकि अपने स्रोत पर ही ऐसे डेटा की बिक्री को चिह्नित किया जा सके। ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों की मदद से डेटा बाजार स्थल का सृजन कर क्षेत्राधिकार को यह अधिकार देगा कि ऐसे डेटा की बिक्री पर स्रोत पर ही कर लगा दिया जाए। भारतीय कर नियम ऐसे तकनीकी बदलावों के साथ तारतम्य बिठाने की अपनी क्षमता बढ़ाने वाले प्रावधान लेकर आ रहे हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर लगाने के तीन बुनियादी अवयवों का जिक्र आलोक प्रसन्न कुमार और विनती अग्रवाल ने किया है। इनमें आय का चरित्र तय करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े गठजोड़ की पहचान और एक स्थायी प्रतिष्ठान (पीई) का वजूद मान लिए जाने के बाद लाभ निर्धारण के नियम बनाना शामिल हैं। कर संधियों में लाभ पर करारोपण का अधिकार दिया जाता है, अगर एक पीई या कारोबारी गठजोड़ स्थापित हो जाए। कारोबारी आय पर 40 फीसदी और रॉयल्टी पर 10 फीसदी कर लगाने का प्रावधान है। कर अधिकारी जहां कारोबारी आय की प्रकृति तय करने को तरजीह देते हैं, वहीं कारोबारी प्रतिष्ठान रॉयल्टी को प्राथमिकता देते हैं। स्पष्ट है कि ग्राहक शुल्क से हुई आय के प्रकृति निर्धारण को लेकर विवाद पैदा होते हैं। भले ही एक पीई का भौगोलिक संबंध होता है लेकिन एक डिजिटल उद्यम को स्थानीय कर्मचारियों की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। इस तरह निष्पादित कार्यों पर आधारित आर्म-लेंथ कीमत पीई जैसी गणनाओं के लिए चुनौती बनी रहती है।

ओईसीडी की अंतिम रिपोर्ट 2020 में आने की संभावना है। यह तीन विकल्पों- समान शुल्क (ईएल), कर कटौती और महत्त्वपूर्ण आर्थिक मौजूदगी (एसईपी) की अवधारणा को स्वीकृति पर गौर करता है। गठजोड़ एवं पीई के साक्ष्य-निर्धारण के लिए गठित एक कार्यबल ने एसईपी अवधारणा का विकास किया था। इस तरह यह भौतिक उपस्थिति से अलग है। एसईपी के तहत राजस्व-आधारित, उपयोगकर्ता-आधारित और डिजिटल कारक शामिल हैं। डिजिटल कारक का आशय स्थानीय डोमेन नेम, स्थानीय डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय भुगतान विकल्प से है और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर लगाने के माध्यम हैं।

भारत का ईएल एक अस्पष्ट प्रकृति और उससे जुड़ी अनिश्चितताओं से ग्रसित है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद ईएल का स्वतंत्र वजूद नहीं रहना चाहिए। ईएल की कटौती आयकर के बरक्स नहीं की जाती है लिहाजा यह दोहरे कराधान का स्रोत हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की डेटा स्थानीयता जरूरत उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए भारत में ही डेटा भंडारण अनिवार्य करती है। फिर भी यह प्रावधान इन कारोबारों को परोक्ष रूप से पीई में तब्दील कर देता है और उन्हें भारतीय कराधान व्यवस्था में शामिल करता है।

अमेरिका और अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाएं इसे डिजिटल अर्थव्यवस्था के इर्दगिर्द घेराबंदी के तौर पर देखते हैं। लिहाजा इस कर एवं दुनिया में इसके इतर स्वरूपों का भावी पथ अनिश्चित बना हुआ है।

कृपा वेंकटेश अप्रत्यक्ष कर, इसके राजस्व संग्रह और मूल्य-वर्द्धित कर या जीएसटी और सीमा शुल्क के गतिरोधों पर गौर करती हैं। जीएसटी उपभोक्ताओं पर लगने वाला ऐसा कर है जिसका सरकार के एजेंट के तौर पर संकलन कारोबार करते हैं। कारोबारों पर ही इसका बोझ डालना इसका मकसद नहीं है लेकिन असल में उन्हें ही कर के संग्रह और बार-बार कर रिटर्न जमा करने की लागत उठाने और रिफंड के लिए इंतजार करने, ऑडिट एवं समीक्षा का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस तरह कारोबारों पर बोझ अभी तक कम नहीं हुआ है।

वस्तुओं के सीमापार कारोबार पर कर लगाना सेवाओं की तुलना में कहीं अधिक आसान है। वस्तुओं के आयात पर लगा जीएसटी कस्टम सीमा पर संग्रह किया जाता है और निर्यात पर कर की दर शून्य है। इस तरह आयातित उत्पादों पर भी घरेलू उत्पाद जितना ही कर लगता है जबकि निर्यात में इनपुट पर कोई कर नहीं लगता है क्योंकि उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है।

हालांकि सीमापार सेवाओं खासकर इलेक्ट्रॉनिक ढंग से दी जाने वाली सेवाओं (ईएसएस) पर कराधान एक चुनौती ही है क्योंकि यह अधिक आसानी से कर से बच सकता है। ईएसएस के कारोबारी मॉडल में टिकटिंग सेवा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड, रेडियो एवं टीवी प्रसारण और दूरसंचार जैसी 'ऑर्डर को मुकाम तक पहुंचाने वाली' सेवाएं आती हैं।

यह एक हाईब्रिड श्रेणी है, मसलन, ऑनलाइन खुदरा एवं होटल बुकिंग ऑनलाइन ऑर्डर को ऑफलाइन तरीके से पूरा करना। उनकी संरचना जटिल होती है जिसमें विभिन्न सेवा प्रदाताओं का स्तर है। आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2(17) में उल्लिखित डिजिटल सेवाओं की एक विस्तृत सूची है जबकि हाईब्रिड उत्पादों का समरूप करारोपण एक चुनौती बनी हुई है।

आपूर्ति एवं उपभोक्ताओं का एक अजीब मेल मसलन, बी2बी या बी2सी भी चिंता का मुद्दा है। अगर उस कारोबार का पंजीकरण नहीं हुआ है तो वह उपभोक्ता यानी सी की ही तरह कर-योग्य है। 'समकक्ष से समकक्ष' श्रेणी में भी दोनों पक्ष गैर-पंजीकृत होते हैं और इसमें एकबारगी या पुराने सामान की बिक्री भी शामिल है। किसी सेवा का ऐसा चरित्र-चित्रण और कराधान के न्याय-क्षेत्र की दृढ़ता चुनौतियां पैदा करती है। संग्रह का असली आधार ही बताता है कि आपूर्तिकर्ता उस क्षेत्र में है या नहीं।

हाईब्रिड मॉडल, खासकर डिजिटल आपूर्ति को निर्धारित करने में कर संग्रह खासा जटिल हो जाता है। वेंकटेश अंतरराष्ट्रीय अदालत में आए मामलों के जरिये अप्रत्यक्ष कराधान की जटिलता को दिखाते हैं। उबर के खिलाफ दायर एक मामले में यह फैसला आया कि उबर की तरफ से दी गई सेवा उसकी प्रमुख सेवा परिवहन का ही हिस्सा है लिहाजा उसे ई-कॉमर्स में नहीं शामिल कर सकते हैं।

ईएसएस पर कराधान में न्याय-क्षेत्र का मसला बढ़ जाता है क्योंकि कारोबार निम्न कराधान वाले देशों में पंजीकरण पर जोर देते हैं। लिहाजा विदेशी ईएसएस की जांच या ऑडिट कर पाना मुश्किल है। ओईसीडी और यूरोपीय संघ ने जीएसटी के प्रभावी संग्रह की व्यवस्था पर मार्गदर्शन दिया है। यहां आपूर्तिकर्ता उस देश का नहीं है जहां पर कर लगना है जबकि आपूर्ति का स्थान ही सेवा पाने वाले की जगह होनी चाहिए।

ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया में नीति-निर्माता डिजिटल अर्थव्यवस्था की सामाजिक उत्पादकता को गंवा रहे हैं। मंदी की तरफ बढ़ते वैश्विक आर्थिक परिवेश में सरकारी व्यय से अधिक आकार होने के बावजूद इसकी चिंता कम ही है। विडंबना की बात है कि अमेरिकी नीति-निर्माता इस प्रक्रिया पर लगाम लगा सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए टिकाऊ समाधान पर हो जोर

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

ऐसा लगता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए मानव इतिहास में इससे बदतर समय नहीं हो सकता था। यह साफ है कि अब स्थितियां हाथ से निकल रही हैं। हर साल नया वर्ष शुरू होने तक हमें बताया जाता है कि यह सबसे गर्म वर्ष है। इसके बाद नया रिकॉर्ड टूट जाता है। जंगलों में आग से लेकर तूफानों के बार-बार आने और उनकी तीव्रता में इजाफा होने, अत्यधिक ठंडी लहरें और अत्यधिक गर्मी जैसी सभी स्थितियां बदतर होती जा रही हैं।

लेकिन हमें इन हालात को काबू में करना होगा। असल तथ्य यह है कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक है, यह घटित हो रहा है और यह हमारे विश्व के गरीबों को और हाशिये पर ला रहा है। भूमि पर काम करने वाले और पानी का इस्तेमाल करने वाले किसान, पशुपालक आदि सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। वे जलवायु परिवर्तन के पीड़ित हैं। दुनिया के गरीबों की इस समस्या को पैदा करने में कोई भूमिका नहीं है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी तकलीफ हमारी दुनिया को ज्यादा असुरक्षित बना देगी। हालांकि उनकी तकलीफ और बढ़ने जा रही है। यही वजह है कि हमें तत्काल इस पर काम करने की जरूरत है।

इनमें से प्रत्येक प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये आपदाएं विकास लाभ को छीन लेती हैं, जिनके लिए सरकार इतनी अधिक मेहनत करती हैं। घर और अन्य व्यक्तिगत संपत्तियां बह जाती हैं, सड़क एवं बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाता है और सभी को फिर से बनाना पड़ता है। यह भी साफ है कि बाढ़ या सूखे का केवल जलवायु परिवर्तन या मौसम में बदलाव से ही लेना-देना नहीं है। हकीकत यह है कि सूखे का संबंध जल संसाधनों के कुप्रबंधन से भी है, जहां पर्याप्त बारिश का पानी फिर से जमीन में नहीं डाला जा रहा है या जल का अकुशल एवं असमान उपयोग हो रहा है। बाढ़ की वजह जल निकासी की योजना नहीं बना पाना, ढालू क्षेत्र में वनों की सुरक्षा की चिंता नहीं करना या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निर्माण और उसे नष्ट करना आदि शामिल हैं। पहले से ही कुप्रबंधित भूमि और कंगाल राजनीति के अलावा खराब मौसम भी हालात को विकट बनाता है।

मैं इसे दोहरी मार मानती हूं। पहले से ही गर्म और जल के अभाव वाली जमीन के लिए उच्च तापमान स्थितियों को विकराल बना रहा है। हरे-भरे क्षेत्र का अभाव मरुस्थलीकरण की स्थितियां बढ़ाता है। वहीं भूमिजल के अतिदोहन और सिंचाई की अच्छी पद्धतियों को नहीं अपनाए जाने से भूमि खराब होती है। इसके अलावा हम जिस तरह से खेती कर रहे है और हम जो खा रहे हैं, उसकी वजह से भूमि का इस्तेमाल बढ़ रहा है। और हम जिस तरह से उगा रहे हैं, उससे वह उत्पादित हो रहा है, जो हम खाते हैं।

जलवायु परिवर्तन और भूमि पर आईपीसीसी की 2019 की रिपोर्ट में यह सही कहा गया है कि आधुनिक कृषि में रसायनों का इस्तेमाल बढ़ा है और इसका औद्योगीकरण बढ़ा है। इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। रिपोर्ट में खानपान में बदलाव की जरूरत बताई गई है, जिनसे हम पृथ्वी पर आसानी से अपना सफर पूरा कर सकेंगे। अब हमारे खानपान और हमारे जलवायु परिवर्तन फुटप्रिंट को जोड़ा गया है।

यह साफ है कि असामान्य मौसम की तीव्रता और बारंबारता में बढ़ोतरी के कारण आपदाओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिससे गरीब और गरीब होंगे। उनकी गरीबी उन्हें भूमि को छोड़कर जीविका के अन्य विकल्प तलाशने पर मजबूर करेगी। उनके पास एकमात्र विकल्प आप्रवास- किसी शहर या अन्य देश में जाना होगा। हमारी वैश्विक दुनिया आपस में जुड़ा हुआ और एक-दूसरे पर निर्भर है। इसे हमें पहचानना होगा।

इसमें मौके मौजूद हैं। अगर हम अपने भूमि और जल के प्रबंधन को सुधार लें तो हम जलवायु परिवर्तन के भयंकर असर से बच सकते हैं। हम सबसे गरीब लोगों के लिए संपत्ति बना सकते हैं और उनकी जीविका सुधार सकते हैं। ऐसा करके हम ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम कर सकते हैं क्योंकि अधिक पेड़ कार्बनडाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे। मिट्टी की सेहत में सुधार से कार्बनडाइऑक्साइड पर अंकुश लगेगा और सबसे महत्त्वपूर्ण कृषि के तरीकों और खानपान में बदलाव से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा। यहीं वास्तविक जवाब छिपा है।

इसलिए हमें गरीबों की अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करना होगा। हमें उनकी क्षमताएं बनानी होंगी ताकि वे न केवल अगली आपदा को झेल सकें बल्कि असल में आपदा पर पार पा सकें। इसके लिए हमें उन पारिस्थितिकी परिसंपत्तियों- रेनवाटर हार्वेस्टिंग से लेकर बेहतर खाद्य प्रणालियों पर निवेश करना होगा, जो ज्यादा टिकाऊ हैं। हमें टिकाऊ शब्द को फिर से परिभाषित करना होगा। आम तौर पर अधिक लागत वाली कृषि पद्धतियां उत्पादक होती हैं, लेकिन टिकाऊ नहीं होती हैं। जब किसानों का कर्ज अधिक होता है तो उनके झटका लगने की ज्यादा आशंका होती है। इसलिए हमें छोटी जोत वाली कृषि पद्धतियों को समझने की जरूरत है, जो बहुफसली, कम लागत वाली और झटकों को झेलने के लिए बनी हैं। हमें उन्हें मजबूत करना होगा, न कि उनकी जगह अपनी पद्धतियां लागू करना। गरीब का ज्ञान कम नहीं है। वे निरक्षर हैं, लेकिन साक्षरों के लिए बहुत बड़े संसाधन हैं। हमारा प्रयास सीखना और देना होना चाहिए।

लेकिन आखिर में मैं पूरे दृढ़विश्वास से यह कहना चाहूंगी कि गरीब या अमीर खुद को बढ़ते तापमान के मुताबिक नहीं ढाल सकते, इसलिए विनाश बड़ा और प्रलयकारी होगा। इसलिए अगर हम कारोबारों को भी अलग तरीके से बनाते या निवेश करते हैं तो हमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने पर कड़े कदम उठाने होंगे। अभी तक दुनिया ने बहुत कम और बहुत देरी से किया है। इस प्रवृत्ति में बदलाव जरूरी है। हम सब के लिए।

कानाफूसी

राजनीतिक दंगल में फंसी पुलिस

समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव राज्य सरकार की आलोचना करने का कोई अवसर नहीं गंवाते हैं, खासकर कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर। हाल में दिन-दहाड़े दो लोगों की हत्या के बाद यादव ने लखनऊ में नए पुलिस आयुक्तालय शुरू करने को महज ढोंग बताया। उन्होंने एक बयान में कहा कि पुलिस प्रशासन का नया ढांचा अपराध पर नियंत्रण करने में असफल रहा है। सपा प्रमुख ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री अपराधियों को खदेड़ने का दावा कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक पदभार संभालने के बाद हरेक जिले में 10 अपराधियों से जूझ रहे हैं। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने भी लखनऊ और नोएडा में पुलिस आयुक्तालय खोलने को महज दिखावा बताया था।

खर्च पर अंकुश

बजट कोष में राज्यों की हिस्सेदारी केंद्र द्वारा कम किए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने खर्च नियंत्रित करने का निर्णय लिया है। अवांछित खर्च पर अंकुश लगाने के लिए अब राज्य सरकार महंगे पांच सितारा होटलों में सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी। इतना ही नहीं, 25 करोड़ रुपये से अधिक रकम का भुगतान बिना वित्त विभाग की अनुमति के नहीं होगा। हाल में ही राज्य के वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि इस वर्ष वित्त का बजट पेश करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती देगी। भनोत के अनुसार केंद्र सरकार ने कर राजस्व में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी में 11,500 करोड़ रुपये तक की कमी की है। इससे विवश होकर राज्य को अपनी नई योजनाओं पर व्यय फिलहाल टालना पड़ा है।

आपका पक्ष

बैंकों की संख्या कम होने से घाटा भी कम

सरकार ने कुछ सरकारी बैंकों के विलय की योजना बनाई है जिससे शायद बैंकों का घाटा कम हो सके। इसके अलावा समय-समय पर घाटे में रहे बैंकों में पूंजी डालने से बचा जा सके। देश में कई सरकारी और निजी बैंक हैं। सभी का मुख्य कार्य राशि जमा करना तथा ऋण प्रदान करना है। बैंक जमा राशि पर कम ब्याज देते हैं तथा ऋण देकर ब्याज से होने वाली आय से कमाई करते हैं। अमूमन सभी बैंकों का कार्य एक समान है तो बैंकों की संख्या बढ़ाने से क्या फायदा। बैंक एक हो लेकिन उसकी शाखाएं अधिक से अधिक संख्या में होनी चाहिए जिससे ग्राहकों को शाखा में अधिक इंतजार नहीं करना पड़े और उनका काम फौरन हो जाए। आज डिजिटल अर्थव्यवस्था का युग आ चुका है तथा सभी कार्य मोबाइल से ही संपन्न हो रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग इसका एक उदाहरण है। मोबाइल से ही किसी को पैसे

केंद्र सरकार ने कुछ सरकारी बैंकों को विलय करने की योजना बनाई है

भेजने, ऑनलाइन खरीदारी करने अथवा पैसे के लेनदेन के कार्य हो रहे हैं। बैंक की शाखा में सिर्फ पैसे जमा करने भर का काम रह गया है। नौकरीशुदा लोगों का वेतन बैंक खाते में आता है जिससे ऐसे लोग शायद ही कभी बैंक की शाखा में जाते होंगे। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग बाकी कसर पूरी कर देती है। इंटरनेट बैंकिंग से कई सारे काम घर बैठे ही हो जाते हैं। अत: सरकार को सभी सरकारी बैंकों का विलय कर एक ही बैंक रखना चाहिए लेकिन उस बैंक की शाखाएं तथा एटीएम हर जगह उपलब्ध करानी चाहिए। ऐसे में बैंकों के अपने खर्च कम होंगे तथा उनका लाभ बढ़ेगा।

निशा राय, मुंबई

स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने का संदेश

दिल्ली विधानसभा चुनाव का एक संदेश भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की परिपक्वता और परिवर्तन का है, जिससे साफ-सुधरी और जनता के मुद्दों पर आधारित चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। लोकसभा चुनावों की विफलता ने अरविंद केजरीवाल को यह भली भांति समझा दिया था कि अब उन्हें राष्ट्रीय राजनीति से दूर रहकर दिल्ली के लोगों की समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केजरीवाल की सत्ता में वापसी से यह निश्चित है कि दिल्ली की जनता को उनके पांच साल का कार्यकाल पसंद आया है। अरविंद केजरीवाल को 'आतंकवादी' कहने वाले नारों ने भी आम आदमी पार्टी को लाभ पहुंचाया है। जनता ने इस प्रकार के नारों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। यह पुरानी बात हो गई है जब केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे और ओछे कटाक्ष किया करते थे और हर समस्या के लिए केंद्र को दोषी ठहराते थे। इस चुनाव में उन्होंने अपनी परंपरागत अराजक और उत्तेजित छवि से बाहर निकल कर एक समझदार राजनेता की तरह व्यवहार किया है। दिल्ली का चुनाव दिल्ली की स्थानीय समस्याओं पर आधारित था। आम आदमी की जीत ने राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर स्थानीय मुद्दों की प्रमुखता को स्थापित कर दिया। इस जीत से यह भी साबित हो गया कि स्थानीय स्तर के मुद्दे जैसे सरकारी स्कूलों में साफ-सफाई, बिजली-पानी की सुलभता और शिक्षा का सुधरा स्तर चुनाव में एक बेहतर रणनीति हो सकती है। इन सब उपायों से सरकार की पैठ हर व्यक्ति और हर घर तक हो गई।

रविंद्र प्रकाश, मुरादाबाद

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

सोने और चांदी में भारी उछाल

कोरोनावायरस से सुरक्षित विकल्पों में बढ़ रही है निवेशकों की दिलचस्पी

राजेश भयानी
मुंबई, 24 फरवरी

सोना-चांदी शार्ष पर

- हाजिर बाजार में सोने की कीमतें 45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 50,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंचने के करीब
- मुंबई में पिछले गुरुवार की तुलना में 1,840 रुपये या 4.4 फीसदी की तेजी के साथ 43,415 रुपये पर बंद हुआ
- सोने के दाम 3 प्रतिशत जीएसटी के साथ 44,717 रुपये तक पहुंचा
- मुंबई के जवेरी बाजार में चांदी 3 प्रतिशत की बढ़त के साथ 49,035 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई

सोने की कीमतों में आज वैश्विक रूप से फिर से बड़ी तेजी देखने को मिली। सोने में आई तेजी ने विश्लेषकों और कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। स्थानीय हाजिर बाजार में सोने की कीमतें 45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 50,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। स्टैंडर्ड श्रेणी का सोना आज मुंबई के जवेरी बाजार में पिछले गुरुवार की तुलना में 1,840 रुपये या 4.4 प्रतिशत की तेजी के साथ 43,415 रुपये पर बंद हुआ। पूर्ववर्ती बंद स्तर की तुलना में यह एक दिन में सबसे बड़ी तेजी है। 3 प्रतिशत जीएसटी के साथ सोने के दाम 44,717 रुपये पर थे।

अंतरराष्ट्रीय कीमतें 1,860 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई हैं और 1,700 डॉलर का स्तर नजदीक है। जल्द ही सोने की कीमत 45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (स्टैंडर्ड गोल्ड-995 शुद्धता) पर पहुंच जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। चांदी में भी तेजी दर्ज की गई। जहां चांदी की अंतरराष्ट्रीय कीमत 18.8 डॉलर प्रति औंस थी, वहीं मुंबई के जवेरी बाजार में यह 3 प्रतिशत की बढ़त के साथ 49,035 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई और जीएसटी के साथ यह 50,000 रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई।

अमेरिका स्थित वरिष्ठ विश्लेषक एवं अरोड़ा रिपोर्ट के लेखक निगम अरोड़ा ने कहा, 'सोने की कीमतों में तेजी कोरोनावायरस के प्रभाव की वजह से आई है, क्योंकि निवेशकों को शेयर बाजार में गिरावट बढ़ने की आशंका से इस धातु में निवेश सुरक्षित नजर आ रहा है। तकनीकी तौर पर सोने में कई वजहों से तेजी देखी जाती है। अक्सर डॉलर में गिरावट की स्थिति में सोने में तेजी आती है, लेकिन अभी जब डॉलर मजबूत हो रहा है, सोना भी चढ़ रहा है। इसी तरह अब जब कोरोनावायरस का डर घट रहा है, सोने में तेजी आ रही है। इस तरह की परिस्थितियों में सोने में तेजी काफी कम देखने को मिलती है।'

बाजार पर चीन में कमजोर वृद्धि और मार्च 2020 की तिमाही में वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताओं का असर दिख चुका है।

हालांकि सोने की ऊंची कीमतों से ग्राहकों में खरीदारी से परहेज करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। सोने के लिए मांग लगभग गायब हो गई है। कुछ शादी संबंधित खरीदारी ही देखी जा रही हैं। पीएनजी ज्वैलर्स के प्रबंध निदेशक सौरभ गाडगिल ने कहा, 'जहां तक निवेश का सवाल है, खरीदार और निवेशक सुरक्षित दांव लगा रहे हैं और वह फिलहाल देखो तथा इंतजार करो की रणनीति अपना रहे हैं।'

सोने की कीमतों में तेजी कब तक बनी रहेगी? इसे लेकर अलग अलग राय हैं। येस सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष हितेश जैन ने कहा, 'चीन में महामारी के आर्थिक प्रभाव से जुड़ी चिंताओं के बीच सोने की कीमतें 1,700 डॉलर प्रति औंस के आसपास हैं। हालांकि हमारा मानना है कि बाजार आखिर धीरे धीरे यह महसूस करने लगेगा कि कि कोरोनावायरस संकट कोई बड़ी वजह नहीं है, बल्कि एक क्षणिक घटनाक्रम है। वित्तीय बाजारों में बढ़ती चिंता हैरान करने वाली है। यह लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती। जब कोरोनावायरस का प्रभाव घटेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा तो सोना मौजूदा ऊंचे स्तरों से नीचे आएगा।'

ब्रेंट क्रूड में गिरावट

कोरोनावायरस का डर धीरे-धीरे वैश्विक बाजार पर पसरता नजर आ रहा है। मिलान और सोल के शेयर बाजारों में सोमवार को भारी गिरावट देखी गई और कच्चे तेल के दाम भी चार प्रतिशत से अधिक गिर गए। उत्तरी लॉम्बार्डी क्षेत्र में 84 वर्षीय एक व्यक्ति की कोरोनावायरस से मौत की खबर आने के बाद सुबह के कारोबार में मिलान में सूचकांक लगभग पांच प्रतिशत गिर गया। लॉम्बार्डी में कोरोनावायरस की वजह से यह तीसरी मौत है।

यूरोप में भी बाजारों की हालत खस्ता देखी गई। फ्रैंकफर्ट शेयर बाजार 3.7 प्रतिशत, लंदन साढ़े तीन प्रतिशत, मैड्रिड 3.3 प्रतिशत और पेरिस 3.8 प्रतिशत तक गिरे हैं। ब्रेंट क्रूड के भाव में 4.1 प्रतिशत जबकि न्यूयॉर्क के वेस्ट टैक्सस इंटरमीडिएट का भाव 4 प्रतिशत तक गिरा है।

इसके विपरीत लंदन सराफा बाजार में सोने का भाव 1,689.31 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया। एजे बेल इन्वेस्टमेंट में निदेशक रस मॉड ने कहा कि कोरोनावायरस के चीन से बाहर फैलने का डर बढ़ा है। इसका असर वैश्विक स्तर पर बाजारों में देखा जा रहा है और इसकी वजह से जिंसों के भाव में भी उतार-चढ़ाव देखा गया है।

दक्षिण कोरिया में भी कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बड़ी है। इसके चलते सोल के शेयर बाजार में 3.9 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं हॉन्गकॉन्ग का शेयर बाजार 1.9 प्रतिशत तक गिर गया है। *भाषा*

चीनी निर्यात कोटे का फिर से आवंटन

रॉयटर्स
नई दिल्ली/मुंबई, 24 फरवरी

उत्पादन में कमी की वजह से कुछ चीनी उत्पादकों द्वारा निर्यात में विफल रहने के बाद भारत ने 600,000 से अधिक टन के गैर-इस्तेमाल वाले चीनी निर्यात कोटे का पुन: आवंटन किया है। कोटे के पुन:वितरण से आने वाले महीनों में दुनिया के इस सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश से निर्यात बढ़ सकता है और इससे वैश्विक कीमतों पर असर देखा जा सकता है जो इस महीने के शुरू में ढाई वर्ष के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थीं।

उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने परिपत्र में कहा है कि मिलों के निर्यात प्रदर्शन की समीक्षा के बाद 611,797 टन के निर्यात कोटे को पुन:वितरित किया गया है। कई वर्षों तक गन्ने की बंपर पैदावार और रिकॉर्ड चीनी उत्पादन से भारतीय चीनी की कीमतें प्रभावित हुई हैं जिससे चीनी मिलों को किसानों का बकाया चुकाना मुश्किल हो गया है। बकाया घटाने और बढ़ते इन्वेंट्री में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार ने 2019/20 सीजन में 60 लाख टन निर्यात के लिए प्रति टन 10,448 रुपये की सब्सिडी मंजूर की है।

लेकिन खासकर महाराष्ट्र से चीनी मिलें उत्पादन में कमी की वजह से चीनी निर्यात में विफल रही हैं, क्योंकि वहां सूखे और बाढ़ से गन्ने की खेती प्रभावित हुई थी।

नैशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाईकनवरे ने कहा, 'सरकार ने सही समय पर निर्यात कोटे के पुन: वितरण की पहल की है। इससे आने वाले महीनों में निर्यात में तेजी आएगी।' नाईकनवरे ने कहा कि भारत 30 सितंबर को समाप्त हो रहे 2019/20 विपणन वर्ष में 50 लाख टन चीनी का निर्यात कर सकता है। भारत ने 2018/19 के लिए 50 लाख टन का निर्यात लक्ष्य तय किया था, लेकिन मिलें केंद्र द्वारा प्रोत्साहनों के बावजूद सिर्फ 38 लाख टन का निर्यात करने में ही सफल रहीं।

एक सरकारी अधिकारी ने नाम नहीं बताने के अनुरोध के साथ कहा कि केंद्र ने मिलों के निर्यात प्रदर्शन की लगातार समीक्षा की है और वह अप्रैल में 300,000 से 400,000 टन का निर्यात कोटा पुन: आवंटित कर सकता है। एक वैश्विक कारोबार कंपनी के मुंबई स्थित डीलर ने कहा कि वैश्विक कीमतों में तेजी से उन मिलों के लिए निर्यात आकर्षक हो गया है जिनके पास अतिरिक्त चीनी मौजूद है। भारतीय चीनी मिल संगठन (इस्मा) ने पिछले सप्ताह कहा कि भारतीय चीनी मिलों ने 2019/20 के सीजन में अब तक 32 लाख टन चीनी निर्यात के लिए अनुबंध किए हैं और लगभग 16 लाख टन की आपूर्ति की जा चुकी है। इस्मा का मानना है कि 2019/20 में देश का चीनी उत्पादन एक साल पहले के मुकाबले 21.6 प्रतिशत घट सकता है जो तीन वर्षों में सबसे निचला स्तर होगा।

50 टन पहुंच सकता है चीनी का निर्यात

खाद्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुबोध सिंह ने कहा कि ऊंची वैश्विक मांग से चालू विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान चीनी का कुल निर्यात 50 लाख टन पर पहुंच सकता है। भारत ने 2018-19 के विपणन वर्ष में 50 लाख टन के अनिवार्य कोटा पर 38 लाख टन चीनी का निर्यात किया था। अधिकारी ने कहा कि इस साल देश का कुल चीनी उत्पादन 2.7 करोड़ टन रह सकता है। इससे पिछले दो वर्ष के दौरान चीनी का उत्पादन 3.3 करोड़ टन रहा था। अभी तक चीनी मिलें 1.6 से 1.7 करोड़ टन चीनी का उत्पादन कर चुकी हैं। इस साल पेट्रोल में एथनॉल के मिश्रण के बारे में सिंह ने कहा कि हम पांच प्रतिशत यानी 1.9 अरब लीटर के स्तर को हासिल कर पाएंगे। हालांकि, इसके लिए नीति 10 प्रतिशत की है। सिंह ने कहा, 'इस साल इसे हासिल करना मुश्किल होगा क्योंकि महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन काफी घट गया है। हालांकि, हम पांच प्रतिशत को हासिल कर पाएंगे।' देश में अभी एथनॉल का उत्पादन 355 करोड़ लीटर है। हालांकि, पेट्रोलियम विपणन कंपनियों (ओएमसी) की जरूरत 511 करोड़ लीटर की है। *भाषा*

पेट्रोल में 10 फीसदी एथनॉल के लिए मूल्य समतुल्यता जरूरी

ब्राजील के एथनॉल विशेषज्ञ पलिनिओ नास्तरी ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनॉल मिलाने का भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, बशर्ते चीनी और एथनॉल के भाव समतुल्य बने रहें। इसके लिए उन्होंने एक दीर्घकालिक मूल्य नीति लागू करने का सुझाव दिया है। मूल्य समतुल्यता का अर्थ है कि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ उत्पाद या सेवा का विक्रय मूल्य भी समान दर से बढ़ना चाहिए।

उन्होंने कहा कि एथनॉल और चीनी के बीच मूल्य समतुल्यता के लिए भारत को दीर्घकालिक मूल्य नीति अपनानी चाहिए। इससे निवेशकों को एक बाजार की दिशा का पता लगेगा और वे एथनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए निवेश करने का निर्णय आसानी से कर सकेंगे।

पिछले साल भारत ने पेट्रोल में पांच प्रतिशत एथनॉल मिलाने के लक्ष्य को हासिल किया था, जो 10 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले काफी कम है। इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सबसे बड़ी बाधा एथनॉल उत्पादन क्षमता की कमी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है, जबकि ब्राजील शीर्ष स्थान पर है। ब्राजील एथनॉल मिलाने के मामले में भारत से बहुत आगे है और वहां पेट्रोल में 25 प्रतिशत एथनॉल मिलाया जाता है। नास्तरी, जो ब्राजील की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति परिषद के सदस्य हैं, ने एक कार्यक्रम में भारत की एथनॉल नीति पर कहा कि ब्राजील में एथनॉल की क्षमता तैयार करने में एथनॉल-चीनी मूल्य समतुल्यता सहित दीर्घावधि की नीतियां सहायक रही हैं। इसी तरह भारत में भी दीर्घावधि की स्थित नीतियां जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि एथनॉल मिश्रण के लिए सही नियामक व्यवस्था होनी चाहिए। *भाषा*

रक्षा सौदे पर आज लगेगी मुहर

ट्रंप बोले, दोनों देश अपने रक्षा संबंधों को विस्तार देने के लिए शानदार कारोबारी समझौते पर काम कर रहे हैं

अजय शुक्ला

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम में जोश-खरोश के साथ स्वागत किया गया जहां करीब सवा लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। ट्रंप ने यहां अमेरिका-भारत रक्षा सहयोग पर चर्चा करते हुए भारत को धरती के सबसे बेहतरीन और घातक सैन्य उपकरण बेचने की पेशकश की।

ट्रंप ने कहा, 'हम सबसे बेहतरीन हथियार बनाते हैं चाहे वह वायुयान, रॉकेट, जहाज या मिसाइल ही क्यों न हो और अब हम भारत के साथ करार कर रहे हैं।' अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे प्रतिनिधि मंगलवार को 300 करोड़ डॉलर का करार करने जा रहे हैं जो बेहतरीन अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों और भारत के सैन्य बलों के लिए जरूरी अन्य उपकरणों से जुड़ा सौदा होगा।'

पिछले दशक में ही अमेरिका भारत के साथ 15-18 अरब डॉलर का रक्षा उपकरणों की बिक्री का सौदा कर चुका है जिनमें सी-130जे सुपर हरक्यूलस और सी-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, पी-8आई पोसाइडन लंबी दूरी समुद्री टोही विमान, हल्के वजन वाले एम777 हॉवित्जर, सीएच-47 एफ चिनूक और एएच-64ई अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। फिलहाल अरबों रकम वाले रक्षा उपकरण पाइपलाइन में हैं लेकिन ट्रंप ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, 'मेरा यह मानना है कि अमेरिका भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार होना चाहिए और अब ऐसा ही हो रहा है।'

अमेरिका और भारत के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को नौसेना में इस्तेमाल होने लायक बहुपयोगी हेलीकॉप्टर 24 सिकोरस्की एनएच-60आर की आपूर्ति के लिए अनुमानत: 2.6 अरब डॉलर के करार पर मुहर लगेगी जो 'रोमियो' के नाम से मशहूर है। हालांकि नौसेना के योजनाकार का कहना है कि

रोमियो की काफी जरूरत महसूस की जा रही है जो भारत के युद्ध पोतों, विध्वंसकों और विमान वाहकों को संचालित कर सके। नौसेना के पास दर्जनों सीकिंग हेलीकॉप्टर हैं जो अब पुराने पड़ चुके हैं। रोमियो अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी (एएसडब्ल्यू) क्षमता से भी लैस है। इसमें दुश्मन की पनडुब्बी की पहचान कर उसे नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा विमान समुद्री क्षेत्र की निगरानी करते हुए वायु से

दोनों देशों के बीच 300 करोड़ डॉलर का रक्षा सौदा होना है

सतह पर मारने वाली मिसाइलों के जरिये दुश्मन के जहाजों को नष्ट कर सकता है। रोमियो नौसेना कमांडो को दुश्मन के तट क्षेत्र में उतार कर उनकी सुरक्षा के लिए कवर फायर भी कर सकता है।

मंगलवार को केवल 24 हेलीकॉप्टरों के करार पर मुहर लगने की संभावना है जो नौसेना के बेड़े के लिए पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि फिलहाल ऐसे 123 हेलीकॉप्टर की जरूरत है।

हालांकि नौसेना रणनीतिक साझेदार कार्यक्रम के तहत देश में ही 99 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए खरीदारी की पहल करेगी। इसके लिए रणनीतिक साझेदार के तौर पर एक निजी भारतीय कंपनी का चयन किया जाएगा जो एक विदेशी वेंडर के साथ साझेदारी कर देश में यह हेलीकॉप्टर तैयार कर सके। सैन्य बेड़े में 24 रोमियो के शामिल होने के साथ ही देश में नौसेना हेलीकॉप्टर तैयार करने के लिए किसी भी खरीदारी प्रक्रिया सिकोरस्की केंद्र में होगा।

हालांकि सीधे खरीदारी के मुकाबले 'मेक इन इंडिया' की प्रक्रिया में लागत 50 फीसदी से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसके लिए मूल वेंडर से निर्माण का लाइसेंस हासिल कर एक नया संयंत्र लगाना पड़ेगा। भारत और अमेरिका छह एएच-64 ई अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर के सौदे को पूरा करने में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं जिसकी अनुमानित लागत 93 करोड़ डॉलर होगी। भारतीय वायुसेना ने पहले ही 22 अपाचे के लिए करार किया है जिनकी आपूर्ति इस साल होनी है।

शानदार स्वागत

नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हवाईअड्डे पर डॉनल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी की अगवानी की

डॉनल्ड ट्रंप को गले लगाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

ट्रंप साबरमती आश्रम में चरखा चलाते हुए

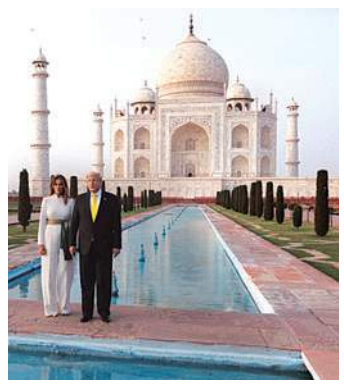

आगरा के ताजमहल का दीदार करने पहुंचे ट्रंप और उनकी पत्नी मिलानिया

अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में जुटी भीड़ का अभिवादन करते प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी और डॉनल्ड ट्रंप

साबरमती आश्रम में ट्रंप और उनकी पत्नी के साथ प्रधानमंत्री मोदी

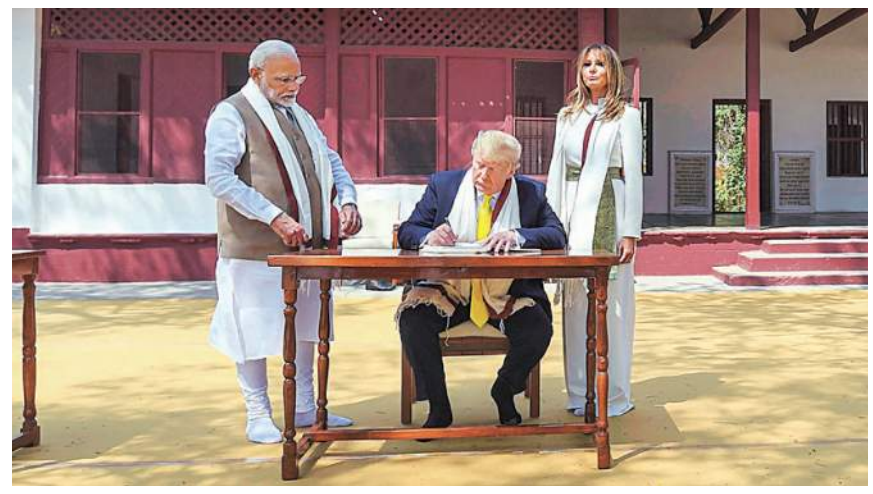

डॉनल्ड ट्रंप ने आश्रम की आगंतुक पुस्तिका में लिखा, 'मेरे अच्छे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस शानदार यात्रा के लिए आपको धन्यवाद।'

'दोनों देशों के बीच संबंध होंगे प्रगाढ़'

पृष्ठ 1 का शेष

ट्रंप ने कहा, 'यह दोनों देशों के लिए बेहतर होगा। वह बहुत सख्त वार्ताकार हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि दोनों देशों की तीनों सेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया जिसे 'टाइगर ट्रायंफ' नाम दिया गया था।'

दूसरी ओर मोदी ने ट्रंप को अपना 'प्यारा दोस्त' बताते हुए कहा भारत और अमेरिका के रिश्ते नैसर्गिक हैं और डिजिटल तथा उद्योग के युग में दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। अमेरिका की भारत के रक्षा क्षेत्र में खासी दिलचस्पी है। वह भारत को विमान, प्रक्षेपास्त्र, रॉकेट, जहाज, सैन्य और असैन्य ड्रोन बेचना चाहता है। ट्रंप ने कहा, 'दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। अमेरिका भारत को पृथ्वी के सबसे बेहतरीन और घातक सैन्य उपकरण देना चाहता है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कल हमारे प्रतिनिधि भारत को अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर और दूसरे सैन्य साजोसामान बेचने के लिए 3 अरब डॉलर के करार पर हस्ताक्षर करेंगे। मेरा मानना है कि अमेरिका भारत का सबसे प्रमुख रक्षा साझेदार होना चाहिए।' चंद्रयान-द्वितीय परियोजना के लिए भारत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहता है।

ट्रंप ने अपने आधे घंटे के भाषण में इस्लामी आतंकवाद, पाकिस्तान, बॉलीवुड और क्रिकेट का जिक्र किया। लेकिन गुजरात में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खोलने के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकते हैं। ट्रंप ने गांवों के विद्युतीकरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार, दूरदराज के इलाकों में रसोई गैस पहुंचाने और साफ सफाई के लिए उठाए गए किए गए प्रयासों पर मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'हर मिनट 12 भारतीयों को घोर गरीबी से बाहर निकाला जा रहा है। यह आश्चर्यजनक है।'

हालांकि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संचालित मोटेरा स्टेडियम में एकत्र हुए अधिकांश लोग ग्रामीण इलाकों से आए थे और ट्रंप का अंग्रेजी में दिया गया भाषण उन्हें लंबे समय तक बांधे नहीं रह सका। साबरकांठा जिले से आए किसान मेघभाई भरवाड़ ने कहा, भाषण ऐसी भाषा में था जिसे हम नहीं समझते हैं। हम तड़के यहां आ गए थे और दोपहर में यहां बहुत गर्मी हो गई थी। भरवाड़ और उनके गांव से आए दूसरे लोगों को अहमदाबाद लाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने बस की व्यवस्था की थी।

इससे पहले ट्रंप अपनी पत्नी मिलेनिया ट्रंप के साथ सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पहुंचे जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी अगवानी की। इसके बाद दोनों नेता साबरमती आश्रम पहुंचे। वहां से उनका काफिला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की तरफ बढ़ा। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग उनकी झलक देखने के लिए उमड़े थे।

मोटेरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम नमस्ते ट्रंप का आयोजन डॉनल्ड ट्रंप अभिवादन समिति ने किया जिसमें कई जाने माने लोग और राजनेता शामिल हैं। इस कार्यक्रम को पिछले साल ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी की तर्ज पर आयोजित किया गया था। हालांकि, गुजरात के कई जिलों से सुबह से ही जुटे लोग ट्रंप का भाषण शुरू होते-होते छंटने लगे थे। हाउडी मोदी कार्यक्रम में जहां दोनों नेताओं ने एकदूसरे का हाथ पकड़कर एरीना का चक्कर लगाया था लेकिन मोटेरा में ऐसा देखने को नहीं मिला। यह कार्यक्रम एक घंटे में ही निपट गया जबकि इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित था।

भारत-अमेरिका के एजेंडे पर ड्रिफ्टवुड परियोजना, कीमत बनी रोड़ा

शाइन जैकब

डॉनल्ड ट्रंप के वर्ष 2017 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा क्षेत्र में संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। भारत हर साल अमेरिका से 12 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात कर रहा है। इसके अलावा जल्द ही एलएनजी का एक अन्य सौदा भी होने के आसार हैं। इस सौदे के तहत भारत को लुसियाना में प्रस्तावित ड्रिफ्टवुड परियोजना से प्राकृतिक गैस में हिस्सा मिलेगा। पेट्रोनेट एलएनजी ने पिछले साल सितंबर में इस परियोजना के लिए अमेरिका की टेलूरियन के साथ सौदा किया था। यह सौदा दो अरब डॉलर से अधिक का है, जिसे ट्रंप के मौजूदा दौरे में अंतिम रूप मिलने के आसार हैं।

पिछले कुछ वर्षों में आयात में बढ़ोतरी के कारण भारत अमेरिका से एलएनजी खरीदने वाला पांचवां सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। लेकिन एलएनजी के दाम गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तरों पर आ गए हैं, जिससे गेल और पेट्रोनेट के लंबी अवधि के करारों की शर्तों में बदलाव पर जोर देने के आसार हैं।

> पिछले कुछ वर्षों में आयात में बढ़ोतरी के कारण भारत अमेरिका से एलएनजी खरीदने वाला पांचवां सबसे बड़ा खरीदार बन गया है

कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने कहा, 'हाजिर और लंबी अवधि के सौदों में अंतर बढ़ता जा रहा है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। हम इस पर उचित समय पर फैसला लेंगे।' इस समय एलएनजी की हाजिर कीमतें 3-4 डॉलर एमएससीएमडी (मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर) पर बनी हुई हैं।

गेल ने लुसियाना में डोमिनियन एनर्जी इंक के कोव पॉइंट प्लांट और शेनियरे एनर्जी इंक के सबाइन पास संयंत्र से हर साल 58

भारत हर साल अमेरिका से 12 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात कर रहा है

लाख टन एलएनजी खरीदने के लिए 20 साल का करार किया है। चालू वित्त वर्ष में जनवरी 2020 तक कुल 27,433 एमएमएससीएम आयात पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.9 फीसदी अधिक था। भारतीय कंपनियां मुख्य रूप से अमेरिकी एलएनजी की अदला-बदली करती हैं क्योंकि आयात की लागत अधिक आती है।

पब्लिसिस सैपिएंट में उपाध्यक्ष (तकनीक) आदित्य गांधी ने कहा, 'पहले एलएनजी के ज्यादातर अनुबंध तेल से जुड़े होते थे और तेल की कीमतें ऊंची होने से एलएनजी की कीमतें भी ऊंची थीं। जब अमेरिकी एलएनजी के अनुबंधों की कीमतों को हेनरी हब गैस कीमत से जोड़ा जाने लगा तो यह आकर्षक विकल्प नजर आने लगा। हालांकि उसके बाद तेल की कीमतें नीचे आई हैं और कुछ ने तेल आधारित और गैस आधारित एलएनजी के अनुबंधों के बीच डेल्टा को घटाने के लिए फिर से सौदेबाजी शुरू की है।' इससे गेल का शेनियरे एनर्जी और डोमिनियन कोव पॉइंट एलएनजी के साथ करार जैसे कुछ पुराने अनुबंधों का आकर्षण घट गया है।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियों के साथ शर्तों पर कड़ी सौदेबाजी करना जरूरी है ताकि भारत में एलएनजी की आयातित लागत अन्य जगहों की तुलना में बहुत अधिक नहीं पड़े। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कच्चे तेल का आयात बढ़ा है। यह 2017-18 में 19 लाख टन था, जो 2018-19 में बढ़कर 62 लाख टन पर पहुंच गया। करीब 42 साल बाद जनवरी 2017 में फिर से अमेरिका भारत के ऊर्जा बास्केट का हिस्सा बना गया है। चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान भारत ने अमेरिका से 54 लाख टन कच्चे तेल का आयात किया है। ईरान और वेनेजुएला से आयात घटने की भरपाई अमेरिका से की गई है।

गांधी ने कहा, 'पिछले छह महीनों के दौरान पश्चिमी एशिया में कई बार अशांति पैदा हुई है, जिससे क्षेत्र में तेल एवं गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंकाएं पैदा हुई हैं। इसलिए भारत के लिए अपनी ऊर्जा आपूर्ति शृंखला को विविधीकृत बनाना महत्त्वपूर्ण है ताकि अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्रोतों को भी शामिल किया जा सके।'

दुनिया में तेजी से फैल रहा कोरोनावायरस

अफगानिस्तान में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया, दक्षिण कोरिया में संक्रमण के मामलों में तेजी

रॉयटर्स

कोरोनावायरस संक्रमण का खौफ सोमवार को बढ़ता नजर आया जब ईरान, इटली और दक्षिण कोरिया में संक्रमण के नए मामले की पुष्टि की गई। हालांकि चीन ने देश के कई हिस्से में आवाजाही में थोड़ी ढील दी क्योंकि यहां संक्रमण के नए मामले में कमी दिख रही है। चीन से बाहर संक्रमण बढ़ने से एशियाई शेयरों और वॉलस्ट्रील में गिरावट देखी गई क्योंकि निवेशक सोना जैसे सुरक्षित विकल्पों में निवेश को तरजीह दे रहे हैं। तेल की कीमतों में भी गिरावट देखी गई जबकि कोरियाई मुद्रा वॉन अगस्त के बाद निचले स्तर पर पहुंच गई।

दक्षिण कोरिया में 231 नए मामलों की पुष्टि हुई जिससे संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 833 हो गई। दक्षिण कोरिया का चौथा सबसे बड़ा शहर देगु संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित

हुआ है और यहां की विमान सेवाएं अगले महीने तक के लिए रद्द कर दी गई हैं।

चीन में संसद सत्र स्थगित

चीन ने घातक कोरोना वायरस के कारण पांच मार्च से शुरू हो रहे अपनी संसद के वार्षिक सत्र को स्थगित करने का सोमवार को निर्णय किया। चीन में इस वायरस से अब तक 2,500 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 77 हजार से अधिक संक्रमित हुए हैं।

ईरान में 43 मामलों की पुष्टि हुई है और आठ लोगों की मौत हुई है। ज्यादा मामले पश्चिम एशिया में सामने आए हैं। बहरीन में पहला मामला सामने आया है। वहीं कुवैत में तीन मामले उजागर हुए हैं। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ईरान पर यात्रा और आव्रजन प्रतिबंध लगा दिए हैं। अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान के पश्चिमी सीमा प्रांत हेरात में कोरोनावायरस का पहला मामला सामने आया है। इस मामले में भी पीड़ित व्यक्ति हाल में ईरान से आया है। विश्व कई सप्ताह से आशंका जता रहा है कि कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली वाले देशों में यह बीमारी पहुंच रही है। यूरोप में इस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रकोप इटली में है। यहां 150 संक्रमण के मामले सामने आए हैं और चौथी मौत हो चुकी है। इटली में शुक्रवार तक केवल तीन मामले सामने आए थे।

एशिया में बड़ा नुकसान

आईएनजी ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा कि कोरोनावायरस फैलने के बाद पर्यटन में मंदी के कारण इस साल एशियाई अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 105 से 115 अरब डॉलर घट सकता है। आईएनजी के एशिया-प्रशांत क्षेत्र के मुख्य अर्थशास्त्री रोबर्ट कारनेल ने कहा, 'अगर हम यह मानकर चलते हैं कि 2020 में चीन में पर्यटकों का आना और वहां से जाना थम जाता है और अतिरिक्त क्षेत्रीय पर्यटन भी कमजोर पड़ता है तो अकेल पर्यटन राजस्व के नुकसान से ही क्षेत्र को करीब 105 से 115 अरब डॉलर का नुकसान होगा।'